● वर्ष-5

● अंक-303

रायपुर, गुरुवार
06 अगस्त 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> डिजिटल सेवा विस्तार धरातल ...

500 करोड़ का एआई मिशन, बीईएमएल प्लांट समेत कई प्रस्ताव मंजूर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस मिशन के तहत - 100 एआई डेटा लैब बनाई जाएंगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज़ बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।

यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बीईएमएल भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु यह राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी।

मंत्रिपरिषद के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में संयंत्र की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला

मंत्रिपरिषद् ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। इस प्रणाली के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक , बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। सी-डैक , पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली को पहले लोक निर्माण विभाग में लागू किया जाएगा, जिसके बाद अन्य निर्माण एवं अधोसंरचना विभागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी, कार्यों की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत बारहमासी सड़कों के निर्माण हेतु जारी

दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधनों के तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण से पूर्व मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है। योजना की पात्रता का दायरा बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया गया है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा अन्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं हैं। आवश्यकता अनुसार नाबार्ड ऋण, पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास मद, खनिज न्यास मद सहित अन्य स्रोतों से भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। कार्यों का अनुमोदन प्रशासनिक विभाग करेगा तथा क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी।

मंत्रिपरिषद् ने वित्त विभाग के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसके तहत Asian Development Bank (ADB) से छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन हेतु "Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्णत: अनुदान प्राप्त किया जाएगा। यह तीन वर्ष (1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029) की बहु-क्षेत्रीय परियोजना है, जिसमें राज्य शासन अथवा भारत सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा।

परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ करना, पीपीपी इकोसिस्टम का विकास, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देना, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार, क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं का विकास तथा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुरूप प्राथमिकता आधारित परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की जाएगी। इसके लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।

यह परियोजना पूर्णत: अनुदान आधारित होने से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तथा इससे संस्थागत क्षमता निर्माण, निवेश संवर्धन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद् ने राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की राशि का अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। अब योजनाओं की राशि विभिन्न बैंक खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रहेगी, बल्कि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से आवश्यकता होने पर ही सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। यह मॉडल भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लागू स्ह्न प्रणाली की तर्ज पर राज्य की योजनाओं में भी लागू किया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

इस व्यवस्था से योजनाओं के क्रियान्वयन की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और निष्क्रिय राशि, गबन तथा बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। साथ ही, राज्य की नकदी प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी, ब्याज का अनावश्यक बोझ कम होगा और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आमजन एवं संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रूपए तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर /बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिंग) किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के विद्युत अवसंरचना विकास को और गति मिलेगी।इसके लिए राज्य शासन द्वारा मूलधन एवं ब्याज के भुगतान पर प्रत्याभूति शुल्क में छूट सहित गारंटी प्रदान की जाएगी।

एनडीए के नए 37 सांसदों को पीएम मोदी की सलाह

जाओ... युवाओं और छात्रों से बातचीत करो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर राज्यसभा में एनडीए के नए व नवनिर्वाचित सांसदों को नाश्ते पर बुलाया था।इस दौरान उन्होंने सांसदों को काम-काज से जुड़े कई सुझाव और नसीहतें भी दी। जिसमें युवाओं और छात्रों से साथ संवाद को बढ़ाने पर जोर दिया। जिसमें ज्यादा से उन्हें सुनने की सलाह दी। साथ ही दिल्ली के मकड़जाल के बचने व अपने लेटर पैड और हस्ताक्षर के दुरुपयोग को लेकर भी सतर्क किया।

पीएम आवास में आयोजित इस नाश्ते में पीएम मोदी ने राज्यसभा में एनडीए के उन 37 सांसदों को बुलाया था, जो हाल ही में नवनिर्वाचित होकर या किसी दूसरे दल से एनडीए में शामिल हुए है। इनमें आम और तृणमूल पार्टी को छोड़कर आए सांसद भी

शामिल थे। हाल ही में आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद भी मौजूद थे।

पीएम ने सदन में अधिकांश समय देने और वहां होने वाली चर्चाओं को ध्यान से सुनने की भी सलाह दी। इनमें पक्ष के साथ विपक्ष की बातों को भी ध्यान से सुनने को कहा। वहीं सभी सांसदों से पुस्तकालय, संसद के संग्रहालय व वहां लगी मूर्तियों आदि को देखने की सलाह दी। पीएम ने इस दौरान कई सांसदों को जब नाम लेकर भी बुलाया, तो अचंभित थे। एक सांसद ने चर्चा में बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि पीएम उन्हें नाम से जानते होंगे।पीएम ने इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों के साथ स्वास्थ्य, योग व समय प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर भी बात की। वहीं बताया कि वह सिर्फ साढ़े तीन घंटे सोते है। वहीं बिस्तर पर जाते ही उन्हें आठ सेकेंड के भीतर नींद आ जाती है। इस दौरान आप से भाजपा में आए सांसद अशोक मित्तल ने पीएम से पूछा कि वह समय का प्रबंधन कैसे करते है।इस पर पीएम ने कहा कि वो जिस पल में रहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। इस दौरान किसी ने पीएम से पूछा कि यात्रा की थकान (जेटलैग) से कैसे निपटते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जैसे ही वो प्लेन में बैठते हैं और जिस देश में गए है, उसी का वक्त लगा लेते हैं, इस तरह से उनको कोई दिक्कत नहीं होती है।

वन महोत्सव-2026 का हुआ शुभारंभ

रायपुर। प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्रीलखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) अरुण कुमार पाण्डेय सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पीपल के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी

नई दिल्ली। फेसबुक, व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण संबंधी कंटेंट के प्रसारित होने, डीपफेक वीडियो के चलने व प्लेटफॉर्म के संचालन में गलतियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को कुछ देर के लिए हटाने के मामले में मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग

ने भारत से माफी मांग ली है।बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा प्रमुख से इस मामले में माफी मांगने के लिए कहा था। बुधवार को जुकरबर्ग की तरफ से माफी मांगने के अलावा मेटा के प्रमुख अधिकारियों की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की।मेटा की तरफ से बताया गया कि बच्चों के यौन शोषण संबंधी कंटेंट के प्रसारण के लिए पेड प्रमोशन के रूप में काफी पैसे दिए गए जिसे खास प्रकार के दर्शकों तक पहुंचाया गया जिसके लिए उन्हें खेद है। मंत्रालय ने मेटा से यह भी साफ कर दिया कि उनके प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरिज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वे कंटेंट के प्रसारण में दर्शकों का चयन करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस दर्शक तक पहुंचाना चाहिए।

प्रमुख समाचार

निशिकांत का मेटा को अल्टीमेटम तीन दिन में माफी मांगें जुकरबर्ग

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाए जाने के मामले पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा को दो टूक शब्दों में तीन दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि

हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय को लिखा है कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना किसी मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) की नहीं, बल्कि पब्लिशर की जिम्मेदारी थी। भाजपा सांसद ने आगे कहा, इसके चलते मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के अंदर माफी मांगनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी मिल रही सेफ हार्बर सुविधा को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसका वे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा, अगर ऐसे कंटेंट से प्रभावित हर व्यक्ति मेटा प्रमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए, तो पूरे देश में एफआईआर की बाढ़ आ सकती है। और जिम्मेदार लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

छात्रों पर कार्रवाई को लेकर राहुल का शाह पर बड़ा हमला

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मॉनसून सत्र के दौरान संसद नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे छात्रों के खिलाफ गलत काम के दोषी हैं। एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि देश के गृह मंत्री अपना चेहरा छिपा रहे हैं

क्योंकि उन्होंने छात्रों के साथ गलत किया है। विपक्ष लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई कथित कार्रवाई का मुद्दा उठा रहा है। यह कार्रवाई 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई थी। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद, सदन में लगातार हंगामे के कारण इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की इस मांग को दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान दें। खड़गे ने कहा कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं।

अभिषेक को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने

उनकी याचिका भी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि पिछली सुनवाई में अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी। अदालत ने कहा था कि अस्पताल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मामले में फैसला किया जाएगा। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह एसएसकेएम अस्पताल नहीं जाएंगे। इसके बाद न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पूरी याचिका खारिज कर दी।

रांची में जेपीएससी परीक्षा विवाद पर 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे

रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है और राज्य विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होने से पहले यहां दो महिलाओं सहित पांच लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये पांचों प्रदर्शनकारी जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले मंगलवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसके साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। इसी स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेन्द्र नाथ महतो का धरना बुधवार को चौथे दिन भी जारी रहा। पिछले 10 दिनों से दोनों समूह 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द करने तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल से जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता जीवन कुमार ने कहा, हमारी मांगों के समर्थन में दो महिलाओं समेत हमारे पांच साथी मंगलवार रात से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।

राहुल गांधी संसद में बहस से भागते हैं : भाजपा

नयी दिल्ली। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बुधवार को तीखा हमला करते हुए उन्हें 'अपरिपक्व' और 'अंशकालिक' नेता प्रतिपक्ष बताया तथा आरोप लगाया कि वह संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं क्योंकि वह नरेन्द्र मोदी सरकार के कामकाज की तुलना पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से होने

से डरते हैं। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस नेता पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धार'' टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राहुल गांधी 'अपरिपक्व', 'अंशकालिक' और 'गैर-जिम्मेदार' नेता प्रतिपक्ष हैं तथा संसद की कार्यवाही इसलिए बाधित कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मोदी सरकार के कामकाज से तुलना होने पर कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। भाटिया ने दावा किया, ''राहुल गांधी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि जब प्रभावशाली मोदी सरकार और 2004 से 2014 तक की रीढ़विहीन कांग्रेस नीत सरकार की तुलना होगी तो चरित्रहीन कांग्रेस बेनकाब हो जाएगी। गांधी ने मंगलवार को पूर्व सांसद वाइको की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कहा था कि देश के छात्र ''गहरी पीड़ा'' में हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माफी नहीं चाहिए।

कोर वोट बैंक पाला बदलने पर यूँ ही मजबूर नहीं होता

नीरज कुमार दुबे

राजनीति में कोई भी दल जब किसी क्षेत्र को अपना अभेद्य किला और वहां के मतदाताओं को अपना स्थायी वोट बैंक मानकर निश्चिंत हो जाता है, तभी उसकी पराजय की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। लोकतंत्र में जनता किसी की बंधक नहीं होती। वह सत्ता देती भी है और उसी सत्ता के अहंकार को ध्वस्त भी करती है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने इसी लोकतांत्रिक सच को एक बार फिर स्थापित कर दिया है। तीन दशक से अधिक समय तक भाजपा के सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत मात्र एक उम्मीदवार की जीत नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता की हार है जो यह मान बैठी थी कि कुछ सीटें और कुछ वोट हमेशा के लिए उसके नाम लिखे जा चुके हैं।

बांकीपुर का जनादेश इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी साधारण विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं था। यह वही इलाका है जहां मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा, सचिवालय और सत्ता के तमाम केंद्र मौजूद हैं। भाजपा का प्रदेश मुख्यालय भी यहीं है। लंबे समय से यह सीट भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक रही है। ऐसे में यहां मिली हार सिर्फ सीट गंवाने की घटना नहीं, बल्कि सत्ता के आत्मविश्वास पर जनता का करारा प्रहार है।सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परिणाम के बाद भाजपा के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हो गया है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि इस चुनाव ने सबसे बड़ा संदेश यह दिया है कि कोर वोट बैंक भी अब स्थायी नहीं रहा। जिस मतदाता को वर्षों तक पार्टी का अटूट समर्थक माना जाता था, उसने इस बार अपना रुख बदलकर बता दिया कि लोकतंत्र में समर्थन किसी दल की जागीर नहीं होता। मतदाता अब काम, व्यवहार और नेतृत्व की शैली के आधार पर फैसला करेगा, न कि केवल पुराने राजनीतिक रिश्तों के आधार पर।

यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि सत्ता का आत्मविश्वास कई बार अहंकार में बदल जाता है और यही चुनावी हार की सबसे बड़ी वजह बनता है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह कुछ नेताओं के बयान सामने आए, उन्होंने भी यह संदेश दिया कि पार्टी अपने गढ़ को लेकर अत्यधिक आश्वस्त थी। लेकिन जनता ने मतदान के जरिए यह बता दिया कि किसी भी मतदाता

को हल्के में लेने की कीमत राजनीतिक दलों को चुकानी पड़ सकती है।

इस हार के पीछे केवल विपक्ष की रणनीति नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर की बेचैनी भी चर्चा का विषय बनी। उम्मीदवार चयन से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक कई फैसलों को लेकर असंतोष की बातें सामने आईं। राज्य की सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी के अंदर जिस तरह की खींचतान दिखाई दी, उसका असर भी चुनावी परिणामों में झलकता नजर आया। यह संदेश भी साफ है कि मजबूत संगठन होने का दावा तभी तक प्रभावी है, जब तक कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व स्वयं को सम्मानित महसूस करे।

मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव ने भी लगभग यही कहानी दोहराई। भाजपा के लिए यह हार केवल कांग्रेस की जीत नहीं थी, बल्कि उसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल खड़े कर गई। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी और मिश्रा समर्थक संगठनात्मक ढांचे का पूरी तरह सक्रिय न हो पाना भाजपा पर भारी पड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस ने स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी, पलायन, खाद की कमी और कथित प्रशासनिक दबंगई जैसे मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया। पार्टी ने चुनाव को सरकार के पक्ष या विपक्ष की लड़ाई बनाने के बजाय स्थानीय जनभावनाओं से जोड़ा और उसी का लाभ उठाया। साफ है कि मतदाताओं ने यहां भी यह संकेत दिया कि किसी एक नेता की राजनीतिक पकड़ या पुराने प्रभाव के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते।वहीं बांकीपुर का संदेश केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। यह उतनी ही बड़ी चेतावनी राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) और देश के अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी है। वर्षों से बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों और परंपरागत वोट बैंकों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस उपचुनाव ने संकेत दिया है कि मतदाता अब नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार है। यदि कोई दल यह मानकर चल रहा है कि कोई विशेष जाति, वर्ग या क्षेत्र हमेशा उसके साथ रहेगा, तो बांकीपुर का परिणाम उस भ्रम को तोड़ने के लिए पर्याप्त है।बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का महत्व भी केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं है। इस परिणाम ने यह संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में वर्षों से हावी जातीय ध्रुवीकरण के बीच अब विकास, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों के लिए भी राजनीतिक जगह बन रही है। भाजपा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरी गढ़ में जीत हासिल कर प्रशांत किशोर ने यह साबित किया कि यदि कोई राजनीतिक दल पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर जनता के वास्तविक सरोकारों को लगातार उठाता है।

नक्सल उन्मूलन में योगदान देने वाले पुलिस अफसरों का सम्मान

गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित, एसपी ने बढ़ाया हौसलां

दंतेवाड़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ राष्ट्रहित में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को सम्मान मिला है. पुलिसकर्मियों के साहस, समर्पण और उल्लेखनीय कार्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सराहा है।इसके बाद दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पुलिस में गर्व और उत्साह का माहौल है। इस सम्मान को न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि, बल्कि पूरी दंतेवाड़ा पुलिस की सामूहिक मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और नक्सल उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह (भा।पु।से।) ने जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन अधिकारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनसुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पुलिस की जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस अवसर पर अधिकारियों को सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई और भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। सम्मानित होने वाले अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र खुंटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर।के। बर्मन, उप पुलिस अधीक्षक राहुल उइके, उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुंभकार, रक्षित निरीक्षक सुशील नौटियाल, निरीक्षक मुकेश ताती, निरीक्षक संजय पोटाम, निरीक्षक संतोष हेमला, निरीक्षक चैतराम गुरुपंच, निरीक्षक रामअवतार पटेल, उप निरीक्षक हजारीलाल मौर्य, उप निरीक्षक लोचन पैकरा तथा उप निरीक्षक कोसा कुंजाम शामिल हैं।इन सभी अधिकारियों ने अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आम नागरिकों के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्राप्त ये सम्मान दंतेवाड़ा पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की कर्तव्यनिष्ठा, साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा का सम्मान है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्य करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन दंतेवाड़ा पुलिस ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया है। यही कारण है कि आज उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिल रहा है।

एसपी ने सम्मानित अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे आगे भी इसी प्रतिबद्धता, पेशेवर दक्षता और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और दंतेवाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ पुलिस का गौरव बढ़ाएंगे।उन्होंने कहा कि यह सम्मान सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भविष्य में बेहतर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेगा।

आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिला लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों और पुलिस के चलाए गए प्रभावी अभियानों, जनसहभागिता और विकासोन्मुख प्रयासों के चलते स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री से सम्मान मिलना न केवल उनकी उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है, बल्कि पूरे पुलिस बल के मनोबल को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।

बिलासपुर केंद्रीय जेल में बढ़ेंगी सुविधाएं

डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण

बिलासपुर। डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने आज केंद्रीय जेल बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कैदियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं को मंजूरी दी। निरीक्षण के दौरान डीजी जेल ने जेल उद्योग, शिक्षा, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें जेल उद्योग के लिए कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन और एलईडी बल्ब व ट्यूबलाइट निर्माण के लिए मशीन सेटअप शामिल हैं।

इसके अलावा जेल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। जेल लाइब्रेरी के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और हितवाद उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कैदियों को पढ़ाई और जानकारी के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने कैदियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जेल बिलासपुर में 20 आरओ वाटर प्यूरीफायर, जेल पाकशाला के लिए ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन और कैदियों के लिए 2000 थाली सेट उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी। वहीं महिला जेल के लिए इन्वर्टर की सुविधा भी मंजूर की गई है।

निरीक्षण के दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने कैदियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

नशे में सड़क पर बस चलाने वाला आरोपी गया जेल

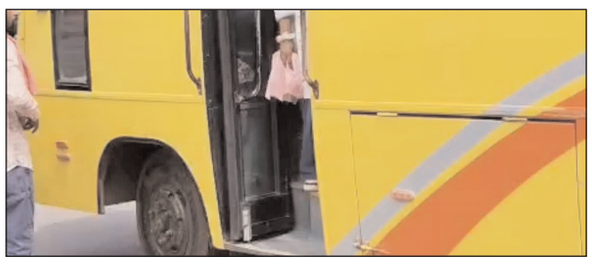

दुर्ग। यातायात पुलिस अक्सर जागरुकता अभियान के जरिए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी बातें बताता रहता है। साल में कई मर्तबा यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और अभियान भी शुरू करता है। बावजूद इसके चंद वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आते। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले ये भूल जाते हैं कि उनकी जान के साथ-साथ दूसरे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। दुर्ग पुलिस ने अब ऐसे शराबी ड्राइवरों को सबक सिखाने की ठान ली है। दुर्ग पुलिस अब नशे में वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज रही है। पुलिस ने एक ऐसे ही ड्राइवर को पकड़ा जो नशे में सवारियों को बिठाकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने बताया कि बीते दिनों राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई रूट पर सवारियों की जान जोखिम में डालकर बस दौड़ा रहे गुरुनानक ट्रैवल्स के ड्राइवर जितेन्द्र देवांगन को पुलिस ने नशे की हालत में पकड़ा था। मौके पर जांच के लिए तैनात उप निरीक्षक भीखम और उनकी टीम ने जब ब्रीथ एनालाइजर से ड्राइवर की अल्कोहल जांच की तो ड्राइवर के भारी नशे में होने की पुष्टि हुई। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले इस लापरवाह चालक को पुलिस ने तुरंत हिरासत में लेकर मामला कोर्ट में पेश किया। सीजीएम कोर्ट दुर्ग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए 3 दिन के साधारण कारावास और 15,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

2 घंटे इंतजार के बाद कलेक्टर से मिले सरपंच

6 सूत्रीय मांगों पर फिर नहीं मिला ठोस आश्वासन

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले के सरपंचों ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर संतन जांगड़े से मुलाकात की। हालांकि लंबी प्रतीक्षा के बाद भी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसे लेकर सरपंचों में भारी नाराजगी देखने को मिली।

कलेक्ट्रेट परिसर में पहले सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायतों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा के बाद 6 सूत्रीय मांगपत्र तैयार किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में सरपंच कलेक्टर से मिलने पहुंचे। बताया गया कि प्रारंभ में कलेक्टर की ओर से ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपने की बात कही गई, लेकिन सरपंच सीधे कलेक्टर से ही मुलाकात पर अड़े रहे।

इस दौरान लगभग दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा। देरी से नाराज सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष लालसाय मरावी कलेक्टर चैंबर के बाहर ही जमीन पर धरने पर बैठ गए। काफी देर बाद कलेक्टर ने सभी प्रतिनिधियों को अपने चैंबर में बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं और ज्ञापन प्राप्त किया।

मनोनीत सरपंचों की नियुक्ति जल्द की जाए।

वर्ष में कम से कम तीन बार कलेक्टर एवं सरपंचों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए।

कुछ निर्माण कार्यों और उनके मानदेय या भुगतान से संबंधित शिकायतें भी हैं तो शासन स्तर से जुड़े विषय हैं उसे आगे भेजा जाएगा।- संतन जांगड़े, कलेक्टर एमसीबी

सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष लालसाय मरावी के नेतृत्व में पहुंचे सरपंचों ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

सरपंचों की प्रमुख 6 सूत्रीय मांगें

ग्राम पंचायतों में लंबित निर्माण कार्यों को तत्काल स्वीकृति दी जाए। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी एवं अन्य लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएं। डीएमएफ योजना के लंबित भुगतान का शीघ्र निराकरण किया जाए। सरपंच एवं पंचों का चार माह से लंबित मानदेय तत्काल दिया जाए।

कलेक्टर ने सुनी समस्याएं

कलेक्टर संतन जांगड़े ने सरपंचों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विषयों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निराकरण जिला स्तर पर संभव होगा, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कोमाखान पुलिस का बड़ा एक्शन, एनडीपीएस एक्ट के तहत 57 लाख का गांजा जब्त

महासमुंद। कोमाखान पुलिस ने नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 114 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की खेप के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गैंग के लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों के पास से एक लग्जरी गाड़ी और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तस्करों के पास से कुल 74 लाख 30 हजार की सामान जब्त किया गया है।

कोमाखान पुलिस ने बताया कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के निर्देश पर जिले में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज थाना कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर एक सफेद रंग की टाटा हैरियर कार (एमएच-48-बीएच-8222) में 3 लोग बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही ग्राम टेमरी जांच नाका पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहनों जांच शुरू की।

संदिग्ध वाहन के पहुंचने पर पुलिस ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर एनएच-353 स्थित कोमाखान चौकड़ी में घेराबंदी कर कार को रोक लिया और तीनों आरोपियों को धरदबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान नागराज पारधी (26 वर्ष), दिनेश माली (28 वर्ष) और सतपाल सिंह राजपूत (38 वर्ष), निवासी शिरपुर, जिला धुले (महाराष्ट्र) के रूप में की। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गांजे की खेप ओडिशा के बालीगुड़ा से लेकर महाराष्ट्र के नारदाना (धुले) पहुंचाने के लिए निकले थे।

कोमाखान थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और गांजे की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। यह कार्रवाई महासमुंद पुलिस की मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जीवित महिला को मृत बताकर जमीन हड़पने की साजिश

सूरजपुर। जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित महिला को कागजों में मृत बताकर उसकी जमीन का नामांतरण और रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। इस मामले में झिलमिली पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन पटवारी सहित चार लोगों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत अपराध भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला के सौतेले बेटे समेत कुछ आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया। इसके बाद उसी आधार पर जमीन का नामांतरण कराया गया और आगे चलकर जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी गई। जब पीड़िता और उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों और पुलिस से की। शिकायत की जांच के दौरान प्रारंभिक स्तर पर दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन पटवारी समेत कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जल संरक्षण की मिसाल तक पहुंचा पाराडोल का बैगा पारा

एमसीबी। पाराडोल के बैगा पारा के ग्रामीणों की रोजमर्रा की मजबूरी थी। गर्मी हो या बरसात, पेयजल के लिए हैंडपंप, नदी और कुओं का सहारा लेना पड़ता था। पानी लाने में घंटों समय और काफी मेहनत लगती थी। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह परेशानी और भी अधिक कठिन थी। लेकिन आज इसी बैगा पारा की तस्वीर बदल चुकी है। ग्रामीण जीवन में सुविधा, स्वच्छता और जागरूकता की नई शुरुआत की है। पाराडोल के बैगा पारा में कुछ समय पहले तक घर के उपयोग के लिए पानी जुटाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती था। पेयजल के लिए दूर स्थित जल स्रोतों पर निर्भरता के कारण ग्रामीणों को रोजाना काफी समय पानी लाने में लगाना पड़ता था। पानी ढोने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर रहती थी। पानी की इस समस्या का असर केवल रोजमर्रा के जीवन पर ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के समय और श्रम पर भी पड़ता था। गांव में पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

आत्मानंद स्कूल के शिक्षक ने बनाया वाइस अटेंडेंस एप

सरगुजा। जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक शिक्षक ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है. जिसमें अटेंडेंस बच्चों की आवाज से लगेगी। इस स्कूल के शिक्षक ऐसे ही नवाचार करते रहते हैं। पहले भी शिक्षक को उनके नवाचारों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। एक बार फिर इस शिक्षक के नवाचार ने युवा पीढ़ी को आधुनिकता से जोड़ने का काम किया है। बतौली विकासखंड के बिलासपुर शिक्षक रोहित गुप्ता ने एआई मॉडल के तहत एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया है, जिसमें बच्चे की उपस्थिति पूरी तरीके से डिजिटली लगेगी। बच्चा जब स्कूल आएगा तो वॉइस के माध्यम से उसका अटेंडेंस लगेगा और उसका पूरा डाटा गूगल शीट में अपडेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को बनाने की मुख्य वजह ये है कि स्कूलों में लंबे समय से रजिस्टर प्रणाली चल रही है ऐसे स्कूल से घर आने के बाद यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा स्कूल आया था या नहीं तो उसके लिए आपको रजिस्टर देखना पड़ेगा। ये रजिस्ट स्कूल बंद होने के कारण आप अगले दिन ही देख सकेंगे।

शराब खरीदते पुलिसकर्मी का कथित वीडियो आया सामने

सूरजपुर। शराब पीकर सड़क और गली मोहल्लों में हंगामा करने वालों को अक्सर पुलिस सबक सिखाती है। लेकिन जब वहीं पुलिस के जवान खुद शराब दुकान से शराब खरीदकर जाते नजर आएं तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होंगे। बालिग इंसान का शराब खरीदना और पीना जुर्म नहीं है, लेकिन जब सरकारी गाड़ी वो भी डायल 112 का जवान शराब खरीदने के लिए अंग्रेजी शराब दुकान पर जाए, तो पुलिस सवालों के घेरे में जरूर खड़ी हो जाती है। घटना सूरजपुर के जयनगर थाना इलाके की है, जहां लटोरी इलाके की शराब दुकान से डायल 112 का जवान शराब खरीदकर ले जाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। कथित वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा, वैसे ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। वीडियो देखने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने तत्काल मामले की जांच करनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस जवान के शराब खरीदने का वीडियो किसी ग्रामीण ने मौके पर बनाकर शेयर कर दिया।

जिले की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक सम्पन्न

एमसीबी। जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े तथा पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के वीसी कक्ष में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में आगामी त्योहारों, सावन सोमवार, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सीमावर्ती चेकपोस्टों की निगरानी, अवैध गतिविधियों की रोकथाम तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सबसे पहले कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने सभी अधिकारियों को आगामी त्योहारों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, जिले की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्टों में सघन निगरानी रखने, वाहनों की नियमित जांच करने तथा खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खैरागढ़ का संगीत विवि बना विदेशी छात्रों की पहली पसंद

23 देशों से आए 253 आवेदन

खैरागढ़। छोटे से शहर खैरागढ़ का नाम अब पूरी दुनिया में तेजी से पहचान बना रहा है। एशिया के पहले राजकुमारी इंदिरा सिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकसंगीत, ललित कला, पेंटिंग, ग्राफिक्स, थियेटर, कत्थक और भरतनाट्यम जैसी पारंपरिक विधाओं की पढ़ाई करने के लिए विदेशों से रिकॉर्ड संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अब तक 23 देशों के 253 विदेशी छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद 17 विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश भी मिल चुका है। प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है और आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त है, इसलिए इस बार विदेशी छात्रों की संख्या पिछले साल से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। इस बार बांग्लादेश, श्रीलंका, अंगोला, ब्राजील, कनाडा, इस्वातिनी, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, लाओस, मेडागास्कर, मॉरीशस, म्यांमार, सीरिया, यमन, नेपाल, अमेरिका, फिलिस्तीन, रूस, सूडान, तंजानिया, ट्यूनीशिया और त्रिनिदाद एंड टोबैगो समेत 23 देशों के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। इनमें सबसे ज्यादा 187 आवेदन बांग्लादेश से आए हैं। इसके अलावा श्रीलंका से 31, मॉरीशस से 6 और रूस से 6 विद्यार्थियों ने भी विभिन्न संकायों में दाखिले की इच्छा जताई है। अब तक जिन 17 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उनमें बांग्लादेश के दो छात्रों ने लोकसंगीत, दो ने ग्राफिक्स, एक ने पेंटिंग, एक ने थियेटर और एक ने कत्थक में प्रवेश लिया है। श्रीलंका के चार विद्यार्थियों ने भरतनाट्यम, एक ने तबला, दो ने थियेटर और एक ने लोकसंगीत को चुना है। वहीं फिजी के एक छात्र को थियेटर और म्यांमार के एक छात्र को ग्राफिक्स संकाय में प्रवेश मिला है। विदेशी विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा रुझान संगीत, ललित कला, पेंटिंग, ग्राफिक्स, थियेटर, कत्थक, भरतनाट्यम और लोकसंगीत की पढ़ाई की ओर है। खास बात यह है कि बड़े महानगरों की बजाय विदेशी विद्यार्थी खैरागढ़ जैसे छोटे शहर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसकी वजह विश्वविद्यालय की गुरु-शिष्य परंपरा, अनुभवी शिक्षक, नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शांत शैक्षणिक माहौल, कम खर्च में पढ़ाई और रहने की सुविधा है। विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय छात्रावास की व्यवस्था भी विदेशी विद्यार्थियों के लिए बड़ा आकर्षण बन रही है।

प्रतीक्षा बस स्टैंड की दुकानों पर अवैध कब्जा

सरगुजा। अंबिकापुर नगर निगम नए बस स्टैंड से कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को मेयर अपनी एमआईसी टीम के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचीं और जिन दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा या दस्तावेजी कमी पाई गई उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये।इस दौरान नगर निगम के सभापति हरमिंदर सिंह ने बताया कि प्रतीक्षा बस स्टैंड से कई दुकानों से राजस्व नहीं आ रहा है, जिसकी जांच करने हम सब यहां पहुंचे तो पाया गया कि कई दुकानें कब्जे में हैं, जिनका दस्तावेज जमा नहीं है, कई दुकानों का पैसा जमा नहीं है। ऐसी दुकानों का चिन्हांकन कर कारवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। मेयर मंजूषा भगत ने कहा बस स्टैंड से शिकायतें आ रही थी जिसके बाद यहां निरीक्षण करने आये थे, यहां देखने पर पता चला की कई जगह मरम्मत की जरूरत है और कई दुकानों पर कब्जा है, हैरत की बात है की बड़े बड़े लोग दुकानों में कब्जा करके रखे हैं। मेयर ने कहा कि इसमें हमारी भी लापरवाही है, निगम में आते ही इस पर संज्ञान लेना था। मंजूषा भगत ने कहा कि इन्ही सबकी वजह से निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर है, निगम को राजस्व नहीं मिल रहा है।मेयर ने कहा कि बस स्टैंड में शौचालय में भी मरम्मत की जरूरत है, सभी का सुधार कार्य होगा और कब्जे को हटा कर दुकानें व्यवस्थित कर राजस्व की हानि रोकी जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

बैज पहले अपनी पार्टी और कार्यकारिणी संभालें, फिर 2028 की बात करें : संजय

रायपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज का बयान मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस में कलेक्टिव लीडरशिप की बात करना वास्तविकता से परे है। कांग्रेस और उसके नेताओं में एकता की बात करना ऐसा है, जिसे जनता लंबे समय से देखती और समझती आ रही है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद तक का इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और आपसी खींचतान हमेशा बनी रही है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज पहले अपने संगठन और अपने विधानसभा क्षेत्र को संभालें, उसके बाद प्रदेश में कलेक्टिव लीडरशिप की बात करें। श्रीवास्तव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष लगभग ढाई से तीन वर्षों में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी तक का गठन नहीं कर पाए, वे आखिर किस आधार पर कलेक्टिव लीडरशिप और 2028 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं?

रेलवे स्टेशन पर 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, जांच के लिए भेजा गया सैंपल

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन स्थित

पार्सल परिसर में बुधवार को करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया। पनीर की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को लेकर संदेह होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (फूड विभाग) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, जब्त किए गए पनीर को रेलवे पार्सल परिसर में रखा गया है। पनीर के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पनीर असली है या नकली तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं। बताया जा रहा कि अमरकंटक एक्सप्रेस से यह संदिग्ध पनीर आया है। पनीर का मालिक कौन है इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यदि जांच में पनीर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा।

विधानसभा ओवरब्रिज के पास बढ़ते हादसों पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिंतित

रायपुर। राजधानी रायपुर के विधानसभा ओवरब्रिज के आसपास लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चिंता जताई है। हाल ही में स्कूल बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत के बाद एसोसिएशन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि विधानसभा ओवरब्रिज के आसपास लगभग 15 से अधिक स्कूल और कॉलेज संचालित हैं, जहां प्रतिदिन 15 हजार से ज्यादा विद्यार्थी स्कूल बसों और अन्य वाहनों से आते-जाते हैं। इसके बावजूद इस व्यस्त मार्ग पर न तो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं और न ही ट्रैफिक पुलिस तैनात रहते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि सड़क किनारे अवैध और बिना अनुमति संचालित दुकानों एवं ठेलों के कारण यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा सड़क से सटी अवैध झुग्गी-झोपड़ियां भी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रही है। वहीं, सड़क पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा भी यातायात में बाधा बनता है, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना तथा कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट 222.ष्द्मष्ठ्वद्य-ह्लह्लह्द.द्बठ्ठ पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नया रायपुर स्थित कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी।

कर्तव्यनिष्ठ होकर जनसेवा एवं सुशासन के लिए करें बेहतर कार्यः साय

मुख्यमंत्री से 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने की सौजन्य मुलाकात, प्रशासनिक सेवा जनविश्वास अर्जित करने का माध्यम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को उनके भावी प्रशासनिक दायित्वों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा में चयन होना उपलब्धि अवश्य है, लेकिन वास्तविक सफलता तब है जब अधिकारी अपने पद का उपयोग जनसेवा, सुशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी शासन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनके निर्णय, व्यवहार और कार्यशैली से आम नागरिक का शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशीलता, पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को अपने कार्य का मूल आधार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करते समय जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी यदि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और

समयबद्ध समाधान की दिशा में कार्य करें, तो प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास स्वतः बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, वन संपदा, उर्वर भूमि और मजबूत ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। इन संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए राज्य को विकसित बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में लंबे समय तक नक्सलवाद बड़ी बाधा रहा, लेकिन सुरक्षा बलों के साहस, केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति तथा जनविश्वास के कारण अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जिन क्षेत्रों में कभी विकास पहुंचना कठिन था, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें विशेष रूप से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में केवल प्रशासनिक दायित्व निभाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भाव भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को चाहिए कि वे शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने सुशासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर शासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजस्व से जुड़े विषय आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। भूमि, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अन्य राजस्व मामलों में लोगों को समय पर राहत मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी की छोटी-सी पहल भी किसी परिवार की बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए अधिकारी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं और प्रत्येक प्रकरण को मानवीय दृष्टि से देखें।

उन्होंने अधिकारियों को व्यवहार में विनम्रता और संयम बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों को सुनना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। कई बार केवल धैर्यपूर्वक शिकायत सुन लेने से ही आधी समस्या समाप्त हो जाती है। यदि अधिकारी जनता से संवाद नहीं करेंगे, तो छोटी समस्याएं भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को जनता के प्रति सहज, सुलभ और उत्तरदायी रहना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके प्रशिक्षण अनुभवों की जानकारी भी ली तथा उन्हें भविष्य में अपने पदेन दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 2025 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का इंडक्शन प्रशिक्षण अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात सभी प्रशिक्षु अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ होकर शासन के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 बैच में कुल सात अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर, संयुक्त संचालक श्रीमती मेनका प्रधान तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।

बृजमोहन अग्रवाल-अमित कटारिया विवाद

अधिकारी सम्मान से करें बात, हिसाब से करें रिस्पांस : अरुण साव

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आईएएस अमित कटारिया के बीच हुआ विवाद तुल पकड़ चुका है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सांसद का पक्ष लेते हुए कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपना एक महत्व है। प्रशासनिक अधिकारी सम्मान से जनप्रतिनिधि से बात करें। बातों को सुने, उस हिसाब से रिस्पांस करें। ये उनका दायित्व है। ये आवश्यक है, और ये करना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 3 साल से जमे कर्मचारियों के तबादले पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश पर मीडिया से चर्चा में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पहले से ही निर्देश हैं। जहां स्पेसिफिक

कंप्लेन आएगी, वहां निश्चित ही संज्ञान लिखा जाएगा।

इस पर कांग्रेस के बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस में तबादला उद्योग चला हैं। वो ऐसे बातें ना करे तो अच्छा है। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर ट्रांसफर होते हैं। प्रशासनिक कसावट और काम में गति के लिए ये जरूरी है।

40 निकायों के लिए राशि जारी होने के बाद भी काम नहीं होने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तेज गति से विकास कार्य हो, काम में विलंब ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम कर रही है। जहां देरी हो रही, उसके कारण क्या हैं? कहां दिक्कत आ रही? इसकी समीक्षा चल रही हैं। विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगे गो बैक के नारों पर अरुण साव ने कहा कि बघेल जी पंजाब गए, वहाँ भी लड़ाई हो रही है। यहां भी कांग्रेसी आपस में लड़ ही रहे हैं। ये लड़ने में ही मशरूफ हैं।

मंत्री राजवाड़े के प्रयासों से 97 गांवों में होगा विद्युत विस्तार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा की विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत भटगांव विधानसभा क्षेत्र के 97 गांवों में विद्युत विस्तार कार्य स्वीकृत किया गया है। लगभग 11.62 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत इस परियोजना के माध्यम से सूरजपुर जिला के दूरस्थ गांवों और मोहल्लों तक विद्युत सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे हजारों ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे।

राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत कार्यों में विकासखंड भैयाथान के 36 गांवों के लगभग 109 मोहल्लों/पारों, विकासखंड ओडग़ी के 32 गांवों के लगभग 68 मोहल्लों/पारों तथा विकासखंड सूरजपुर के 29 गांवों के लगभग 53 मोहल्लों/पारों में विद्युत विस्तार किया जाएगा। यह परियोजना विशेष रूप से उन ग्रामीण और जनजातीय बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां अब तक पर्याप्त विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्य, पेयजल व्यवस्था, कृषि आधारित गतिविधियों तथा ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास की रोशनी को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वीकृति भटगांव विधानसभा के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि हर घर और हर आंगन तक बिजली पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी।

शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि यह जमानत कई शर्तों के साथ मिली है।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को राज्य से बाहर रहने समेत अन्य शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अनवर ढेबर शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें अन्य मामलों में भी आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच शराब कारोबार में कथित सिंडिकेट बनाकर अवैध तरीके से धन अर्जित किया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, शराब की खरीद दरों में कथित हेरफेर, बिना हिसाब वाली शराब के निर्माण और एफएल-10ए लाइसेंस के जरिए कमीशन वसूली जैसे तरीकों से अवैध कमाई की गई। मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर से जुड़ी कई संपत्तियों को अटैच किया था। इनमें रायपुर स्थित जमीनें और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से जुड़ी हुई हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अदालत में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है।

अपराधियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर ज्ञान देना हास्यास्पद : भाजपा

रायपुर। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले पांच वर्षों के भूपेश बघेल शासनकाल में छत्तीसगढ़ को अपराध, माफियाराज और भ्रष्टाचार की मण्डी बना दिया था, उसके नेताओं का आज कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाना सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा राज्य की कानून-व्यवस्था पर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए इसे बेहद हास्यास्पद, अवसरवादी और राजनीतिक ढोंग करार दिया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासनकाल में अपराधियों को खुलकर सत्तावादी संरक्षण प्राप्त था। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का कांग्रेसीकरण - यही कांग्रेस का वास्तविक राजनीतिक चरित्र रहा है। भूपेश सरकार के समय संगठित गिरोहों, शराब माफिया, सट्टा-जुआ और गांजा-अफीम के अवैध कारोबारियों को जिस तरह से शासकीय और राजनीतिक संरक्षण मिला, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को अपराध की भट्ठी में झोंक दिया था। बैज के आरोपों का करारा जवाब देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आज जो कांग्रेस नेता नशे के कारोबार और अपराधों की दुहाई दे रहे हैं, वे शायद भूल गए हैं कि राज्य में नशे के नेटवर्क का तंत्र और अवैध कारोबार का ढाँचा उन्हीं की भूपेश सरकार के दौरान फैला और पनपा। कांग्रेस शासन में थानों का राजनीतिकरण कर दिया गया था और पुलिस प्रशासन का उपयोग केवल विरोधियों को दबाने तथा सत्ताधारियों के अवैध धंधों को संरक्षण देने में किया जाता था। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका कोई भी राजनीतिक रसूख क्यों न हो! कांग्रेस नेता अनर्गल बयानबाजी करने और जनता को गुमराह करने के बजाय अपने अतीत के कारनामों पर आत्ममंथन करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता यह भली-भाँति जानती है कि प्रदेश में अपराध का बीजारोपण किसने किया था?

प्रदेश में 1460 गौधामों की होगी स्थापना

■ 88 गौधामों का पंजीयन पूर्ण

रायपुर। गौधाम योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति, कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार गोधन संरक्षण और बेसहारा मवेशियों की देखभाल के लिए गौधाम योजना को राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है, जिससे गौसेवा की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ ही पशुधन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर को 1460 गौधाम योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम चरण में ऐसे गौठानों का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है एवं जहां समस्त आवश्यक अधोसंरचना पूर्ण हैं। गौधाम योजना के प्राप्त 408 आवेदनों में से 151 को

प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, जिसमें पंजीयन पूर्ण कर पशुओं के व्यवस्थापन की कार्यवाही की जा रही है।

गौधाम योजना अंतर्गत ऐसी शासकीय भूमि जहां अधोसंचना पूर्ण हो एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप हो, जैसे गौठान को चिन्हांकित कर स्वयं सेवी संस्था, पंजीकृत गौशाला, एन.जी.ओ. एफ.पी.ओ. ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाना है। वर्तमान में 88 गौधामों का पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है और 42 गौधामों में लगभग 5109 पशुधन संरक्षित है। कलेक्टर/जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा, पंचायत द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला स्तर पर गठित समिति के भौतिक सत्यापन पश्चात, गौधाम के आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को प्रेषित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन आयोग के क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा हेतु प्रत्येक 03 माह में एक बार आयोजित बैठक में विस्तृत समीक्षा की जाती है, तत्पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जाती है।

प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात आयोग के साथ अनुबंध एवं पंजीयन पश्चात जिला प्रशासन के माध्यम से गौधाम में घुमन्तू पशुओं का व्यवस्थापन किया जाता है। पशुधन विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग नियम संशोधित कर गौधाम संचालन हेतु ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी गई। साथ-साथ शहरी गौठान को भी योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं शासन द्वारा स्वीकृत योजना में गौधाम निर्माण के लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं, परन्तु अध्यक्ष गौ सेवा आयोग द्वारा परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक विकास खण्ड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का चयन कर पूरे प्रदेश के 1460 गौधामों की स्थापना की जाएगीं। ग्राम पंचायत के माध्यम से गौधाम संचालन के नियम संशोधन एवं शहरी गौठानों को भी योजना में शामिल करने के पश्चात निश्चित रूप से भविष्य में गौधाम के संख्या में बढोतरी होगी। आवश्यकता अनुसार जिलों से गौधाम स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो. नि. वि. वि/यां संभाग रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक 3819/NIT-10/2026-2027/व ले लि दिनांक 03/08/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन.आई.ई.टी. क्र./ निविदा क्र.	कार्य का नाम NO of Call	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
10 T0044	लो. नि. वि. (वि/यां) उपसंभाग धमतरी के अंतर्गत विश्राम भवन एवं विश्राम गृह के भवनों में स्थापित समस्त एयर कंडीशनर हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य प्रथम आमंत्रण	2.24
10 T0045	लो. नि. वि. (वि /यां) उपसंभाग धमतरी के अंतर्गत जिला प्रशासन के प्रमुख गैर आवासीय भवनों में स्थापित एयर कंडीशनर हेतु वार्षिक रख रखाव का कार्य। प्रथम आमंत्रण	1.90
10 T0046	लो. नि. वि. (वि./यां) उपसंभाग धमतरी के अंतर्गत न्याय प्रशासन के प्रमुख गैर आवासीय भवनों में स्थापित एयर कंडीशनर हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य प्रथम आमंत्रण	1.90
10 T0047	Providing and fixing lightening arrester system to District Jail Building at Dhamtari, Distt Dhamtari Chhattisgarh प्रथम आमंत्रण	0.54
10 T0048	Providing line shifting of 11 KV line, Transformer DP and LT line for construction of Govt College building at Silouti under CSPDCL DC Amdi of CSPDCL Sub Dn Arjuni and CSPDCL Dn Dhamtari, Block Kurud, Distt Dhamtari CG प्रथम आमंत्रण	6.36
10 T0049	Providing shifting of 11 KV line and 11 KV line DP for construction of bridge on Kajal River at village Jabarra on Nagri Jabarra road under CSPDCL DC Gattasilli of CSPDCL Sub Dn Belargaon and CSPDCL Dn Dhamtari, Block Nagri Distt Dhamtari CG प्रथम आमंत्रण	5.01
10 T0050	Comprehensive annual maintenance contract of passenger lift installed at office of Chief Engineer E/M zone Raipur and Chief Engineer bridge construction zone Raipur under PWD E/M workshop subdivision, Raipur CG प्रथम आमंत्रण	3.20
10 T0051	लो.नि.वि.(वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में लगे हुए एयर कंडीशनर का वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य। प्रथम आमंत्रण	5.61
10 T0052	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में न्यू कन्वेंशन हॉल भवन में एयर कंडीशनर का वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य। प्रथम आमंत्रण	5.90
10 T0053	लोक भवन में स्थापित समस्त एयर कंडीशनर हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य। प्रथम आमंत्रण	10.00

नोटः- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी दिनांक 18/08/2026 अपरान्ह 5:30 बजे तक

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें-1) उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

कार्यपालन अभियंता

जी-262702558/3

लो. नि. वि. वि/यां संभाग रायपुर छग

उपचुनाव जनादेश: क्या बदल रहा है मतदाता का मिजाज?

योगेश कुमार गोयल

लोकतांत्रिक राजनीति में कई बार छोटे चुनाव भी बड़े संदेश दे जाते हैं। विधानसभा उपचुनावों को लंबे समय तक केवल रिक्त सीटों को भरने की औपचारिक प्रक्रिया माना जाता रहा है। सामान्य धारणा यही रही कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है, प्रशासनिक बढ़त, संगठनात्मक शक्ति और सत्ता के प्रभाव के कारण वही दल उपचुनाव आसानी से जीत जाता है। इसी कारण उपचुनावों के परिणामों को व्यापक राजनीतिक संकेतक के रूप में कम ही देखा जाता था किंतु पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा तेजी से बदली है। अब उपचुनाव केवल एक सीट का फैसला नहीं करते बल्कि जनता के तत्कालीन मनोभाव, सरकार के प्रति संतोष-असंतोष, संगठन की मजबूती, नेतृत्व की स्वीकार्यता और भविष्य की राजनीतिक दिशा के संकेत भी देते हैं। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनावों ने भी यही संदेश दिया है। तीन सीटों में से दो पर भाजपा की हार और केवल एक पर जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या ये केवल स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम हैं अथवा भाजपा के सामने उभर रही नई राजनीतिक चुनौतियों का प्रारंभिक संकेत? उपचुनाव सत्ता परिवर्तन का जनादेश नहीं होते किंतु वे जनता के बदलते मानस की पहली आहट अवश्य होते हैं और यही कारण है कि इन परिणामों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। सबसे अधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही। यह सीट केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं थी बल्कि भाजपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। लगभग तीन दशक से यह भाजपा का अभेद्य दुर्ग रहा। पहले भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन के पिता और बाद में स्वयं नितिन नवीन लगातार यहां विजय प्राप्त करते रहे। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई और भाजपा को अटूट विश्वास था कि उसका यह गढ़ सुरक्षित रहेगा किंतु जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने न केवल भाजपा का यह किला ध्वस्त कर दिया बल्कि बिहार की राजनीति में नए विकल्प की संभावनाओं को भी मजबूत कर दिया। यह परिणाम केवल भाजपा की हार नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक चूक का भी परिणाम माना जा रहा है। उम्मीदवार चयन में अंतिम समय तक बना भ्रम, स्थानीय कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि और अत्यधिक आत्मविश्वास ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। लंबे समय तक किसी सीट पर लगातार जीत कभी-कभी संगठन में आत्मसंतोष पैदा कर देती है। यही स्थिति बांकीपुर में दिखाई दी। भाजपा ने शायद मान लिया था कि उसका पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक नेटवर्क किसी भी परिस्थिति में जीत सुनिश्चित कर देगा जबकि मतदाता पहले की तुलना में अधिक सजग और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बन चुका है। बांकीपुर का परिणाम प्रशांत किशोर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में अनेक दलों को सफलता दिलाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं चुनावी परीक्षा में उतरे और सफल हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह विफल रही थी किंतु इस विजय ने सिद्ध कर दिया कि यदि कोई दल लगातार जनता के बीच बना रहे और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए तो वह स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे सकता है। यह जीत बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को भी बल देती है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की दतिया सीट भाजपा के लिए और अधिक चिंता का विषय है। भाजपा की यह हार केवल विपक्ष की सफलता नहीं बल्कि भाजपा संगठन के भीतर असंतोष की अभिव्यक्ति भी मानी जा रही है।

प्रशांत किशोर की जीत के सियासी मायने चौंकाने वाले

कमलेश पांडे

जन सुराज पार्टी के संस्थापक व मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को लगभग 19 हजार वोटों से तगड़ी शिकस्त देकर न केवल चुनाव जीता, बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। प्रशांत किशोर की यह जीत केवल एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखी जा रही है।

ऐसा इसलिए कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के तीन दशक से अधिक पुराने गढ़ में अकल्पनीय जीत दर्ज की है और अपनी जन सुराज पार्टी को पहली बड़ी चुनावी सफलता दिलाई है। हालांकि, एक उपचुनाव के परिणाम के आधार पर पूरे राज्य के चुनाव के जनादेश का संकेत मान लेना एक बड़ी सियासी गलतफहमी होगी। फिर भी, उनकी यह जीत कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 वोटों के भारी अंतर से हराया है।

लिहाजा, बांकीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि, बिहार की राजनीति अब केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की दोध्रुवीय प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि जन सुराज ने स्वयं को एक संभावित तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

दूसरा बड़ा संदेश यह कि, जनसुराज पार्टी की नई जीत जहाँ भाजपा नीत एनडीए के लिए इस अकल्पनीय पराजय के बाद संगठन और रणनीति की समीक्षा का गहरा अवसर पैदा करता है। वाकई प्रशांत किशोर की जीत भाजपा के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है, क्योंकि बांकीपुर जैसी भाजपा की पारंपरिक सीट का उसके हाथ से एक झटके में निकल जाने से यह साफ संकेत मिलता है कि चुनाव जीतने के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण और मतदाता की अपेक्षाएं भी निर्णायक हो सकते हैं।

तीसरा बड़ा संदेश यह कि, इस अकल्पनीय जीत से जन सुराज पार्टी को राजनीतिक वैधता मिली है। अब जन सुराज को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि चुनाव जीतने में सक्षम

राजनीतिक दल के रूप में देखा जाएगा। वाकई जिस चुनौती भरे सियासी परिदृश्य में प्रशांत किशोर ने अपनी जीत का परचम लहराया है और भाजपा के लंबे समय से सुरक्षित माने जाने वाले बांकीपुर के गढ़ में 30 साल बाद ही सही, पर सेंध लगा डाली है; वह नवोदित पार्टी के लिए एक अहम उपलब्धि है। इससे भाजपा का मनोबल टूटने के पुष्ट संकेत मिले हैं।

चौथा बड़ा संदेश यह कि, जन सुराज पार्टी की पहली चुनावी जीत का सेहरा खुद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के सिर पर ही बंधा है और वो अपना पहला चुनाव लड़कर ही विधायक बनकर विधान सभा पहुंच चुके हैं, जिससे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करने के उनके मिशन को काफी बल मिला है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की नई भूमिका की चर्चा अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से विधायक बनने के बाद उन्हें विधानसभा के भीतर अपनी राजनीति और वैकल्पिक नीतियों को सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

पांचवां बड़ा संदेश यह कि, जहाँ तक 2026 में हुए बांकीपुर बिहार विधानसभा उप चुनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात है तो यह परिणाम जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा और आगामी चुनावों में उम्मीदवारों व समर्थकों को आकर्षित कर सकता है। चूंकि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनावों में शुरुआती धमाल मचाने के बाद प्रशांत किशोर की रणछोड़ रणनीतिकार और बुजदिल राजनेता वाली जो छवि बनी थी, अब उससे उन्हें मुक्ति मिली है और वह एक जुझारू राजनेता के रूप में उभरे हैं।

छठा बड़ा संदेश यह कि, जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के इस सियासी उभार से एक नई युवा और शहरी राजनीति के संकेत मिले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में रोजगार, शिक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रकार यदि यह रुझान अन्य क्षेत्रों में भी दिखता है, तो इससे बिहार की चुनावी राजनीति में मुद्दा-आधारित प्रतिस्पर्धा और मजबूत हो सकती है।

सातवां बड़ा संदेश यह कि, विपक्षी राजनीति भी अब एक नई करवट लेगी। उसे एक नया सकारात्मक विकल्प मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से राजद नीत महागठबंधन का वोट बैंक जनसुराज की ओर यकायक शिफ्ट हुआ, यह उसके समक्ष भी अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखने की एक तगड़ी चुनौती समुपस्थित करता है। इससे राजद और महागठबंधन के सामने भी अब एक नई चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि यदि जन सुराज पार्टी आगे भी विपक्षी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इससे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए विपक्ष का निर्विवाद केंद्र बने रहना कठिन हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कि बांकीपुर में राजद तीसरे स्थान पर रही।

आठवां बड़ा संदेश यह कि, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रांत में भाजपा की यह पराजय उसके नेताओं की आपसी रस्साकशी का निराशाजनक परिणाम तो है ही, लेकिन उलजुलूल समीकरणों को साधने की उसकी राजनीतिक फितरत, और इसके चक्कर में बिगड़ैल बोलों पर बरती गई रणनीतिक खामोशी का यह साइड इफ़ेक्ट्स भी समझा जा सकता है। यह घटनाक्रम पुन: भाजपा को खुली नसीहत देता है कि यदि बनावटी %ओबीसी राजनीति% के चक्कर में वह अपनी मूल राजनीतिक सवर्ण सियासी पूंजी भी न गंवा बैठे, जो कि कांग्रेस की ऐसी ही क्षुद्र सियासत से आजिज आकर भाजपा की ओर 1990 के दशक में शिफ्ट हुआ था, और अब विकल्प मिलते ही भाजपा की क्षुद्र सियासी चाल को भी नया राजनीतिक पाठ पढ़ाने पर आमादा दिखता है।

नवां बड़ा संदेश यह कि, बिहार में सत्ता मिलते ही नवभाजपाइयों यानी राजद से भाजपा में आए नागमणि जैसे सामाजिक विषधर नेताओं ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को धत्ता बताकर बैकवर्ड-फॉरवर्ड की जो लोहियावादी सियासत परवान चढ़ानी चाही, उसका साइड इफेक्ट्स भी

बांकीपुर उपचुनाव में दिखा है। क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर को जातिवादी नजरिए से देखना और वैसी ही गोलबंदी को परोक्ष शह देकर बैकफुट पर लौटने से सवर्णों के बीच गलत संदेश गया है। इसलिए भाजपा के ओबीसी-दलित नेताओं को धुर सवर्ण विरोधी मानसिकता से बचना होगा, अन्यथा प्रतिक्रिया वश सवर्ण यदि ओबीसी की राजद और दलितों की लोजपा रामविलास को सियासी शह दे देंगे तो भाजपा के ओबीसी-दलित नेता न घर के रहेंगे, न घाट के।

दसवां बड़ा राजनीतिक संदेश और स्वाभाविक सवाल यह है कि भाजपा के %पैराशूट% राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा खाली की गई इस प्रतिष्ठित सीट पर बीजेपी चुनाव कैसे और क्यों हारी? क्या इसके पीछे भी उसकी कोई बड़ी रणनीति है या फिर अपने बड़े नेताओं के खिलाफ हुई भितरघात की वजह से भाजपा को यह शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी। चूंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी प्राय: उपचुनाव नहीं हारती है, इसलिए यदि भाजपा हारी है तो इससे भी कई बड़े सवाल उपजते हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बांकीपुर में हुई चुनावी हार भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार की हार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्वमुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बड़बोले केंद्रीय मंत्री गण चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की संयुक्त हार है, क्योंकि सबने एक दूसरे के साथ सियासी घात-प्रतिघात किया है, ताकि सूबाई राजनीति में गठबंधन साथियों की प्रासंगिकता बनी रहे।

इस नजरिए से यह एनडीए के उन सूबाई सहयोगियों की भी हार है जो भाजपा के आधार वोट बैंक से अपने चुनाव दर चुनाव तो जीतते हैं, और फिर जीत के बाद मंत्री बनकर भी भाजपा के ही कोर सवर्ण वोटर्स को चिढ़ाने वाली (राजद/कॉंग्रेस वाली) भड़काऊ टिप्पणी शुरू कर देते हैं, जिस पर भाजपा की खामोशी उसकी ओबीसी-दलित परस्त राजनीति के समक्ष घुटने टेकते प्रतीत होती है। इससे उसका प्रतिबद्ध सवर्ण कैडर इधर उधर भागने के विकल्प ढूंढता है और वह मिलते ही भाजपा को उसकी असली सियासी औकात समझा देता है।

बहरहाल, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि महज एक उपचुनाव के परिणाम से आप पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2030 का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते; बल्कि इसके व्यापक निष्कर्ष के लिए आगे के संसदीय आम चुनाव 2029 के चुनावी रुझानों को भी देखना समझना दिलचस्प होगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वह भी अधिकांश पुराण-प्रतिपादिक पार्थिव भूगोल का ही समर्थन करता है। यदि वर्तमान गवेषकों की पड़ताल में और पौराणिक-भूगोल में एक अंश तक कुछ अन्तर भी दीख पड़ता है तो वह जड़वादी गवेषकों की अनुसन्धान पद्धति के अधूरेपन का ही दोष है। ज्यों ही ये लोग अपनी अनुसन्धान पद्धति की अपूर्णता को दूर कर पाएंगे त्यों ही पुराण-प्रतिपादित भूगोल के साथ सर्वांश में सहमत हो जाएंगे।

सात-द्वीप

हमारी इस पथ्वी पर सात द्वीप पाये जाते हैं, यथा- जम्बूद्वीप (यूरेशिया) शाक-द्वीप (आस्ट्रेलिया) कुश-द्वीप (दक्षिणी अमेरिका) क्रौंच-द्वीप (उत्तरी अमेरिका) शाल्मली द्वीप (ग्रीन लैण्ड) प्लक्ष-द्वीप किंवा गोमध-द्वीप (श्रऔन्टरैक्टिका विक्टोरिया लैण्ड आदि और पुष्कर-द्वीप (अफ्रीका)।

वर्तमान भूगोलवेत्ता सज्जन यूरेशिया, अफ्रीका, ग्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका इन पाँचों को महाद्वीप मानते हैं। शेष भूखण्डों को उपद्वीप के नाम से पुकारते हैं, परन्तु वेदव्यास जी ने पुराणग्रन्थों में त्यक्तानुबन्धे सामान्यग्रहणम् इस नियम के अनुसार महा और उप दोनों अनुबन्धों को त्याग कर विशिष्ट भूखण्डों को सामान्यतया द्वीप नाम से ही याद किया है अतएव उनकी संख्या सात ठहती है, परन्तु जो जो भूखण्ड अत्यन्त छोटे किंवा प्रायद्वीपों की भान्ति तत्तत् द्वीपों से सटे हुये हैं उन्हें पुराणों में उन उन निकटवर्ती द्वीप के उपद्वीप माना है, जैसे हमारे जम्बूद्वीप के लंका सिंहल आदि आठ उपद्वीप बतलाये हैं।

सात समुद्र

यद्यपि पृथ्वी के समस्त खण्डों को आवेष्टित करने वाली जलराशि को जलत्वसामान्येन एक ही समुद्र कहा जा सकता है।

क्रमशः ...

बल-बुद्धि और गति में हनुमानजी की बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं

डॉ. नरेन्द्रकुमार मेहता

श्रीराम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से कहा कि महर्षि! इसमें सन्देह नहीं कि बालि और रावण के बल की तुलना नहीं थी परन्तु मेरा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमानजी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव इन सभी सद्गुणों ने हनुमानजी के भीतर घर कर रखा है। ये महाबाहु वीर धैर्य से एक ही छलांग में सौ योजन समुद्र को लाँघ गए। रावण के अन्त:पुर में गए। अशोक वाटिका में सीताजी से मिले, उनसे वार्तालाप कर धैर्य बँधाया। अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री, कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्षय को मार गिराया। तदनन्तर ये मेघनाद के नागपाश से

बँधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात् इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। लंकापुरी को जलाकर भस्म किया। मुनीश्वर! मैंने तो इन्हीं के बाहु-बल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज तथा सीता, लक्ष्मण मित्र और बन्धुजनों को प्राप्त किया है।

एतन्मे भगवन् सर्वं हनूमति महामुने।
विस्तरेण यथातत्वं कथयामरपूजिता।
वाल्मीकिरामायण उत्तरकाण्ड सर्ग 35-13

देवबन्धु महामुने! भगवन! आप हनुमानजी के विषय में ये सब बातें यथार्थरूप से विस्तारपूर्वक बताइए।

श्रीरामचन्द्रजी के ये युक्तियुक्त वचन सुनकर अगस्त्यजी हनुमानजी के समक्ष यह बोले- श्रीराम! हनुमानजी के विषय में आप जो कुछ कहते हैं, वह सब सत्य ही है। बल-बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान सूर्य के वरदान से जिनका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरू नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमानजी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम से विख्यात पत्नी थीं। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यन्त व्याकुल होने के कारण बालक (शिशु) हनुमान जोर-जोर से रोने लगे। उन्हें लाल रंगवाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमानजी ने उन्हें कोई फल समझा और वे उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछल पड़े। उन्हें उड़ता देख देवताओं, दानवों और यक्षों को बड़ा आश्चर्य हुआ।

अपने पुत्र को सूर्यदेव की ओर जाते देखकर दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव (पवनदेव) भी बर्फ के ढेर की भाँति शीतल होकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है इसे गुण-दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं को भी बहुत सा भावी कार्य होना है अत: उन्हें जलाया नहीं। बालक हनुमान को देखकर इन्द्र को अधिक क्रोध नहीं आया। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इन्द्र ने बालक हनुमान पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इन्द्र के वज्र की चोट खाकर हनुमान एक पहाड़ पर गिरे वहाँ गिरते समय इनकी बायीं ठुड्डी टूट गई।

पीओके की पुकार और दुनिया की जिम्मेदारी

ललित गर्ग

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इन दिनों जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वे केवल एक चुनावी प्रक्रिया की कहानी नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनविश्वास के गहरे संकट की दास्तान हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति निष्पक्ष चुनाव, नागरिक स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही में निहित होती है, लेकिन जब चुनाव भय, हिंसा, प्रशासनिक दबाव और धांधली के आरोपों से घिर जाएँ, तब लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाता है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति इसी कठोर वास्तविकता की ओर संकेत करती है। वहाँ के लोगों का आक्रोश केवल चुनावी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक भेदभाव और नागरिक अधिकारों की अनदेखी के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि वहाँ का असंतोष अब स्थानीय मुद्दा न रहकर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान हो। यदि किसी क्षेत्र में चुनाव पहले से तय परिणामों का माध्यम बन जाएँ, यदि सत्ता का पूरा तंत्र एक दल विशेष के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, यदि विरोध की आवाज को बलपूर्वक दबाया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में समय-समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता का प्रभाव प्रशासन और चुनावी व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जनता के मन में यह विश्वास ही समाप्त हो जाए कि उसका मत परिवर्तन ला सकता है, तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही समाप्त हो जाता है।

पाकिस्तान स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, लेकिन उसके व्यवहार में लोकतंत्र की मूल भावना बार-बार प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का सम्मान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है। यदि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी या व्यवस्था विरोधी बताकर दबाने का प्रयास किया जाए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए और यदि प्रशासन जनता के बजाय सत्ता के हितों की रक्षा करता दिखाई दे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता स्वत: समाप्त होने लगती है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति आज उसके लोकतांत्रिक दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद वहाँ का सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिजली संकट, महँगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की कमी और विकास की धीमी गति ने जनजीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह विडंबना है कि जिन नदियों से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी क्षेत्र के लोग लंबे समय तक बिजली कटौती झेलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके विकास के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जनता के भीतर असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है।

लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि वह संकट के समय जनता के साथ किस प्रकार खड़ा रहता है। यदि जनता की शिकायतों का समाधान संवाद से करने के बजाय दमन से किया जाए, तो यह शासन की कमजोरी का प्रमाण होता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, वे चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि संवाद होता है। दुर्भाग्य से जब शासन संवाद छोड़कर शक्ति प्रदर्शन का मार्ग अपनाता है, तब जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो जाती है। विश्व समुदाय के सामने भी यह एक गंभीर नैतिक प्रश्न है। यदि लोकतंत्र और मानवाधिकार वास्तव में सार्वभौमिक मूल्य हैं, तो उनका संरक्षण केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और महाशक्तियाँ अनेक अवसरों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा की बात करती हैं। यदि यही सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उठ रहे प्रश्नों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। मानवाधिकारों का मूल्य भौगोलिक सीमाओं से निर्धारित नहीं होता। जहाँ भी नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान प्रभावित होता है, वहाँ वैश्विक समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे।

भारत ने हाल की घटनाओं के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति की ओर आकर्षित किया है और वहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा दमन रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार की अपील को केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया पर लगातार प्रश्न उठ रहे हों, यदि नागरिक असुरक्षा और अविश्वास के वातावरण में जी रहे हों और यदि उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों, तो विश्व समुदाय की निष्क्रियता भविष्य के लिए और भी गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक नीतियों का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक ओर वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र, न्याय और जनाधिकारों की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में उन्हीं मूल्यों को व्यवहार में उतारने में विफल दिखाई देता है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली से सिद्ध होती है। यदि नागरिक स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित और असहाय महसूस करें, तो लोकतंत्र का दावा खोखला प्रतीत होने लगता है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सत्ता परिवर्तन की संभावना, स्वतंत्र संस्थाएँ, निष्पक्ष प्रशासन और नागरिकों की गरिमा की रक्षा है। यदि ये तत्व अनुपस्थित हों, तो चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हों। मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, राजनीतिक दल समान अवसर प्राप्त करें और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास पुनर्स्थापित हो। यह केवल उस क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति के लिए भी आवश्यक है। विश्व की महाशक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल वक्तव्यों से नहीं होती। जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर पड़ती हैं, वहाँ समय रहते निष्पक्ष निगरानी, संवाद और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए रचनात्मक प्रयास आवश्यक होते हैं।

आज का इतिहास

1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए।
1951 कोरियाई सेना पश्चिमी कोरिया में चार दिनों तक सीधे अपने सहयोगियों के साथ लड़ी। अमेरिकी आठवीं सेना ने भोर में दुश्मन का सामना किया और कोरियाई बलों ने जवाबी हमले के साथ जवाब दिया।
1955 फ्रांस के दक्षिणी और अंटार्कटिक क्षेत्र को एक विदेशी क्षेत्र के रूप में बनाया गया।
1956 डुमोंट, दुनिया के पहले टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है, जिसने इसके कार्यक्रम को प्रसारित किया।
1960 क्यूबा ने देश के सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया।
1962 जमैका में यूनाइटेड किंगडम का साम्राज्य समाप्त हुआ और उसे स्वतंत्रता मिली।
1962 जमैका ने यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, अंग्रेजी के 300 वर्षों के बाद मोरीथन ने स्पेनिश उपनिवेशवादियों से इसे1655 पर कब्जा कर लिया।
1964 अमेरिकी शोधकर्ता डोनाल्ड करी ने प्रोमेथियस को काटकर एक ब्रिसलकोन पाइन ट्राइकाउन किया था, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह सबसे पुराना ज्ञात क्लोनल जीव था, जिसकी खोज कम से कम 4,862 साल पुरानी थी।
1966 शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान अबूधाबी के अमीर और शासक बन गए, अपने भाई, शेख शाहबुत बिन सुल्तान अल नाहयान को, जो एक रक्तहीन तख्तापलट में दर्शाया गया था, सफल हुए।
1988 न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस अधिकारियों ने पहले 24 घंटे टॉमपकिंस स्क्वायर पार्क में विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ पर आरोप लगाया, एक दंगा भड़काने के कारण पुलिस की बर्बरता की 100 से अधिक शिकायतें हुईं।
2008 प्रवेश 31 टीवी पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रसारण बंद किया गया।
2008 मॉरिटानियन के राष्ट्रपति सिदी मोहम्मद औलद शेख अब्दल्लाही को उच्च-श्रेणी के जनरलों के एक समूह द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया था, जो कि उन्होंने कई घंटे पहले कार्यालय से अलग किया था।
2009 स्वाइन फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास में इस्लामी पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान सभी तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब ले जाता है।
2010 रूस के प्रधान मंत्री, व्लादिमीर पुतिन, रूसी इतिहास में सबसे खराब सूखे के कारण 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक आटा और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं।

तमिलनाडु : उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी से उठे कई सवाल

विनोद पाठक

दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। राज्य में राजनीतिक संघर्ष केवल चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं रहा, अपितु सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कई बार व्यक्तिगत टकराव का रूप लेती रही है। राज्य की राजनीति में प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस जांच, अदालतों में मुकदमे और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अक्सर चर्चा का विषय बनते रहे हैं।

समय-समय पर यह आरोप लगते रहे हैं कि सत्ता में आने वाली सरकारें अपने विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती हैं। तमिलनाडु की राजनीति को कई राजनीतिक विश्लेषक %प्रतिशोध की राजनीति% का उदाहरण मानते हैं।

दरअसल, द्रमुक के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन एक सार्वजनिक सभा में दिए विवादित बयान को लेकर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। उनके भाषण को लेकर राज्यभर में शिकायतें दर्ज कराई गईं। पुलिस ने मंगलवार को जूनियर स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया।

पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गर्मा दिया। समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि विरोधियों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। कानून सभी के लिए समान है।

यह पूरा घटनाक्रम केवल एक विवादित बयान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे राज्य की राजनीति का वह लंबा इतिहास है, जिसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कई बार व्यक्तिगत संघर्ष का रूप ले लेती है। यहां सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता है। विरोधियों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर बहस शुरू हो जाती है। यही कारण है कि यहां की राजनीति को समझने के लिए उसके इतिहास और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है।

राज्य में राजनीति केवल राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं रही। यहां राजनीति लंबे समय तक ऐसे करिश्माई नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिन्होंने फिल्मों और जनआंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। द्रविड़ आंदोलन से निकले नेताओं ने सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और तमिल भाषा के सम्मान को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। यहां नेता केवल राजनेता नहीं, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़े जननायक भी बन गए।

यदि इतिहास पर नजर डालें तो द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच दशकों तक चली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) के द्रमुक से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद राज्य की राजनीति दो ध्रुवों में बंट गई। इसके बाद करुणानिधि और जे. जयललिता के बीच चला लंबा राजनीतिक संघर्ष कई बार व्यक्तिगत कटुता तक पहुंच गया।

वर्ष 2001 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की देर रात हुई गिरफ्तारी की तस्वीरें पूरे देश ने देखीं। उस घटना ने यह संदेश दिया कि तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता परिवर्तन केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर राजनीतिक विरोधियों पर भी दिखाई देता है।

इसी इतिहास ने राज्य की राजनीति में एक ऐसी संस्कृति विकसित कर दी, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बीच विश्वास की कमी लगातार बढ़ती गई। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आरोप वही रहे, विरोधियों पर मुकदमे, जांच एजेंसियों की सक्रियता और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप। आज भी जब किसी बड़े नेता के खिलाफ पुलिस या कानूनी कार्रवाई होती है तो उस पर केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी चर्चा होती है।

राज्य की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सिनेमा का प्रभाव है। शायद देश का कोई दूसरा राज्य ऐसा नहीं है, जहां फिल्मों और राजनीति का रिश्ता इतना गहरा हो। सी.एन. अन्नादुरई, एम. करुणानिधि, एमजीआर और जे. जयललिता से लेकर अभिनेता विजय तक, अनेक लोकप्रिय फिल्मी हस्तियों ने राजनीति में कदम रखा तथा व्यापक जनसमर्थन हासिल किया। यहां फिल्मी लोकप्रियता कई बार राजनीतिक पूंजी में बदल जाती है। अभिनेता का प्रशंसक धीरे-धीरे राजनीतिक समर्थक बन जाता है। यही कारण है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े विवाद भी कई बार राजनीतिक विवाद बन जाते हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में होने वाला हर बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। द्रमुक लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति का एक महत्वपूर्ण दल रहा है।

लोकसभा में उसके सांसदों की संख्या और दक्षिण भारत में उसका जनाधार उसे राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली बनाता है। ऐसे में राज्य में होने वाली हर बड़ी राजनीतिक या कानूनी कार्रवाई का असर दिल्ली की राजनीति तक महसूस किया जाता है।

उदयनिधि स्टालिन से जुड़े विवाद ने भी यही संकेत दिया है कि अब तमिलनाडु की राजनीति केवल द्रमुक और उसके विरोधियों की लड़ाई नहीं रह गई है। राज्य में नए राजनीतिक दलों की सक्रियता, बदलती सामाजिक अपेक्षाएं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी राजनीतिक समीकरणों को नया रूप दे रही हैं। हर दल अब अपनी रणनीति नए सिरे से तय कर रहा है। उदयनिधि की गिरफ्तारी के घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन इसके साथ भाषा की मर्यादा और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

राजनीतिक भाषणों में कटाक्ष, आलोचना और वैचारिक विरोध लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन जब भाषा व्यक्तिगत या अमर्यादित हो जाती है तो विवाद पैदा होना तय है। ऐसे मामलों में कानून अपना काम करता है। अदालतें अंतिम निर्णय देती हैं। इसलिए किसी भी मामले को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना भी उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। द्रमुक विपक्ष की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले कुछ वर्षों से तमिलनाडु में अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। भाजपा लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह राज्य में एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन सकती है। ऐसे में यदि राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है तो उसका लाभ किस दल को मिलेगा, यह भविष्य की राजनीति तय करेगी।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसमें सत्ता और विपक्ष, दोनों की भूमिका बराबर महत्वपूर्ण होती है। यदि सत्ता पक्ष कानून का उपयोग केवल राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए करता हुआ दिखाई दे या विपक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन न करे तो दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकतीं। इसलिए यह आवश्यक है कि जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्य करें। किसी भी कार्रवाई का आधार केवल कानून और उपलब्ध साक्ष्य हों, न कि राजनीतिक दबाव।

नितिन के गढ़ में किशोर : प्रशांत के लिए बांकीपुर की जीत उत्साहजनक

ज्योति भास्कर

लोकतंत्र में उपचुनावों को अक्सर केवल रिक्त सीटों को भरने की औपचारिक प्रक्रिया मान लिया जाता है, लेकिन कई बार यही छोटे चुनाव बड़े राजनीतिक संदेश लेकर आते हैं। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों के उपचुनावों ने भी यही साबित किया है। तीनों ही सीटों के नतीजों ने राजनीतिक दलों के संगठन, नेतृत्व, उम्मीदवारों के चयन और जनभावनाओं को समझने के संबंध में अहम संकेत दिए हैं।

सर्वाधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही, जहां भाजपा के तीन दशक पुराने गढ़ को ध्वस्त करते हुए प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी पहली बार विधानसभा तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में प्रशांत किशोर की यह जीत कितनी प्रभावशाली रही, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि मतों की गिनती के पहले से लेकर अंतिम चरण तक एक बार भी भाजपा प्रत्याशी उनसे आगे नहीं बढ़ सका।

बांकीपुर की जीत दरअसल उस राजनीतिक प्रयोग की पहली ठोस सफलता है, जिसे प्रशांत किशोर पिछले कुछ वर्षों से बिहार में खड़ा करने कोशिश कर रहे थे। यही जन सुराज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 238 में से 236 सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी थी। लिहाजा, इस जीत का श्रेय प्रशांत किशोर को मिलना ही चाहिए, पर इसके लिए भाजपा की अपनी रणनीतिक भूलें कोई कम जिम्मेदार नहीं। पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाना, फिर उनसे नामांकन वापस कराते हुए आनन-फानन में एक अनजान चेहरे को मैदान में उतारे जाने से कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिससे

मतदाताओं में पार्टी की छवि पर भी यकीनन असर पड़ा होगा।

दूसरी ओर, प्रशांत किशोर ने ई-20 और खासकर पटना में नीट परीक्षा आंदोलन जैसे मुद्दों से उपजी नाराजगी को प्रभावी ढंग से अपने पक्ष में मोड़ लिया। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने राज्य में अपनी मजबूत स्थिति जरूर साबित की है, लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली हार एक बार फिर भाजपा के भीतर पनप रही असंतुष्टि को दर्शाती है।

पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के निर्णय ने पार्टी के एक बड़े वर्ग को असहज किया, जिससे पूरे चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कथित भितरघात की चर्चाएं लगातार होती रहीं। यह संदेश भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं का आंतरिक असंतोष और भितरघात जैसी प्रवृत्तियां चुनावी मैदान में घातक साबित हो सकती हैं। प्रशांत किशोर के लिए यह जीत उत्साहजनक है, पर इस जीत का श्रेय जितना उनको है, उतना ही भाजपा की रणनीतिक भूलों को भी है। भाजपा के लिए ये नतीजे आत्ममंथन का अवसर जरूर हैं।

क्या अब संसद नहीं, सड़क से तय होगी देश की राजनीति?

सिद्धेश्वर शुक्ला

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र और अन्य मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर चल रहा अनशन समाप्त हो गया। यह आंदोलनकारियों की सफलता तो है ही, साथ ही इसे सरकार की भी एक उपलब्धि माना जा सकता है कि उसने इस आंदोलन को बिना किसी जनहानि के समाप्त करा दिया और 2020-21 के दिल्ली किसान आंदोलन तथा 2024 के पंजाब-हरियाणा किसान आंदोलनों की तुलना में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी अपेक्षाकृत बहुत कम क्षति पहुंची।

हालांकि, इस आंदोलन से भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख लेना भी आवश्यक है, ताकि ऐसे जनांदोलनों की परिस्थितियों, संचार-रणनीतियों और जनभावनाओं को समय रहते समझकर उनसे अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। एक समय था जब संचार के माध्यमों (साधनों) पर सत्ता का व्यापक नियंत्रण हुआ करता था और आंदोलनों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती थी कि आंदोलनकारी इन साधनों तक अपनी पहुंच किस सीमा तक बना पाते हैं। किंतु सोशल मीडिया के वर्तमान युग में यह स्थिति मूलत: बदल चुकी है। आज संचार के साधनों तक जितनी पहुंच सत्ता की है, लगभग उतनी ही पहुंच एक सामान्य व्यक्ति की भी संभव हो गई है, विशेष रूप से भारत जैसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में।

प्रभावी संदेशों का निर्माण कर उन्हें सही समय पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला ही इस संचार-प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर लेता है। इसी कारण अब

आंदोलनों के विमर्श की लड़ाई जमीन से अधिक सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। संभवत: इसी बदलते संचार-संतुलन से उत्साहित होकर चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र से हारने के बाद अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, कहते हैं कि अब देश की राजनीति संसद से नहीं, बल्कि सड़क से तय होगी। यह कथन केवल आंदोलनकारी राजनीति के बढ़ते आत्मविश्वास को ही नहीं दर्शाता, बल्कि उस नई संचार-व्यवस्था की ओर भी संकेत करता है जिसमें सोशल मीडिया ने सड़क पर होने वाले छोटे से आंदोलन को भी कुछ ही समय में व्यापक राजनीतिक विमर्श में बदलने की क्षमता प्रदान कर दी है।

सीजेपी के आंदोलन का सबसे अभद्र पक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता, केंद्रीय मंत्रियों, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों को उनकी माता, बहन तथा परिवार की अन्य महिलाओं के जननांगों का नाम लेकर अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां देना रहा। तथाकथित जेन-जी के कुछ युवक-युवतियों ने न केवल सार्वजनिक रूप से निर्लज्जता के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किए।

चिंताजनक यह भी है कि सीजेपी के नेताओं ने न तो मंच से ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास किया और न ही सोशल मीडिया अथवा सार्वजनिक बयान के माध्यम से अब तक इसकी निंदा की।

सरकार और समाज को समझना होगा कि जेन-जी केवल आंदोलनकारी नहीं हैं। इसी पीढ़ी के युवा अपनी मेहनत और योग्यता से आईएएस, आईपीएस, पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भी सेवाएं दे रहे हैं। एक ओर सरकारी सेवा में कार्यरत इन युवाओं पर अनुशासन और आचरण के कठोर नियम लागू हैं, जिसके कारण वे उकसावे और गालियों के बावजूद संयम बनाए रखने को बाध्य हैं।

दूसरी ओर उनके ही समवयस्क आंदोलनकारियों को ऐसी अभद्रता की खुली छूट नहीं दी जा सकती। कानून की दृष्टि में दोनों की गरिमा समान होनी चाहिए। इसलिए सरकार को वर्तमान कानूनों में आवश्यक संशोधन कर सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर आंदोलनों के दौरान, किसी व्यक्ति की माता, बहन, बेटी, पिता, पुत्र अथवा अन्य परिजनों के जननांगों का उल्लेख कर अपमानित करने के उद्देश्य से दी जाने वाली लक्षित अश्लील गालियों के लिए एक से तीन वर्ष तक की सजा का स्पष्ट प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए। अभिव्यक्ति और असहमति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन उसकी आड़ में किसी की व्यक्तिगत और पारिवारिक गरिमा को तार-तार करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती।

अपने पक्ष की स्थापना के लिए सुदृढ़ संदेशों का प्रयोग और प्रतिपक्ष के विचारों का खंडन करना शास्त्रार्थ का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किंतु सोशल मीडिया के इस युग में यह शास्त्रार्थ आमने-सामने बैठकर नहीं, बल्कि युवाओं के वैचारिक संसार में हो रहा है।

यह संभव है कि युवा दोषपूर्ण संदेशों से प्रभावित होकर उसी के अनुरूप व्यवहार और कार्य करने लगें। ऐसे में उनके वैचारिक संसार में प्रवेश कर दोषपूर्ण संदेशों का तर्कपूर्ण खंडन करना और उनके स्थान पर अधिक तथ्यपरक एवं प्रभावी संदेशों की स्थापना करना भी एक सुदृढ़ संचार-रणनीति के माध्यम से ही संभव है।

वस्तुत: सत्ता अब केवल पांच वर्ष में एक बार चुनाव के समय जनता को अपने विचारों से प्रभावित कर जनादेश प्राप्त करने और उसके आधार पर अगले पांच वर्ष तक सरकार चलाने का विषय नहीं रह गई है। सोशल मीडिया और युवा-आधारित आंदोलनों के इस दौर में सत्ता को बनाए रखना पूरे पांच वर्ष चलने वाले सतत वैचारिक संघर्ष और जनसंवाद का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। इसके लिए सरकार को जनता के बीच जाकर सीधा संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है।

इस रणनीति में सोशल मीडिया के साथ-साथ जमीनी स्तर पर रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनसंचार माध्यमों का भी समुचित उपयोग किया जा सकता है। इससे युवाओं को तथ्यों के आधार पर अपना मत बनाने का अवसर मिलेगा। यदि सरकार शास्त्रार्थ की मूल भावना- तर्क, तथ्य, संवाद और प्रतिपक्ष के विचारों के विवेकपूर्ण खंडन के साथ इस रणनीति पर आगे बढ़ती है, तो सोशल मीडिया आधारित इस आंदोलन का शांतिपूर्ण और संवादपरक समाधान संभव हो सकता है।

भारत-चीन रिश्ता क्या वाकई सुधर रहे हैं?

नीरज कुमार दुबे

ऐसे समय में जब भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की बातें हो रही हैं, वर्षों बाद सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ है और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद भी तेज हुआ है, उसी बीच चीन में रह रहे भारतीयों ने ऐसी शिकायतें सामने रखी हैं, जिन्होंने सबको चौंका दिया है। भारतीयों का कहना है कि चीन के सोशल मीडिया पर भारत और भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री तेजी से बढ़ रही है, भारतीय पेशेवरों को नौकरी के वीज़ा मिलने में मुश्किलें आ रही हैं और उनके जीवनसाथियों के रोजगार पर भी कई तरह की पाबंदियां हैं। इतना ही नहीं, भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने नई दिल्ली से ऐसी मांग भी कर दी है, जिसने दोनों देशों के संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

हम आपको बता दें कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने हाल के वर्षों में पहली बार भारतीय समुदाय के साथ %ओपन हाउस% कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत के राजदूत विक्रम दोरईस्वामी, काउंसलर (कॉन्सुलर, शिक्षा एवं सामुदायिक मामलों) नितिनजीत सिंह और काउंसलर (वीजा) रमेश सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीयों से सीधे संवाद किया। इस बातचीत में भारतीय समुदाय ने जिन मुद्दों को सबसे प्रमुखता से उठाया, वह भारत-चीन संबंधों के वास्तविक हालात की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं।

भारतीयों ने शिकायत की कि चीन के सोशल मीडिया मंचों पर भारत, भारतीय संस्कृति और भारतीय खान-पान को लेकर अपमानजनक और भड़काऊ सामग्री तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना था कि यह केवल ऑनलाइन ट्रोलिंग का मामला नहीं है, बल्कि इससे चीन में रह रहे भारतीयों के सामाजिक माहौल और सुरक्षा की भावना पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा भारतीय पेशेवरों को नौकरी के लिए वर्क वीज़ा मिलने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने यह भी बताया कि उनके जीवनसाथियों को रोजगार की अनुमति नहीं मिलने से परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। कुछ लोगों ने दूतावास से जुड़ी काउंसलर सेवाओं में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों का मुद्दा भी

उठाया।

राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने इन चिंताओं को गंभीर बताते हुए कहा कि चीन सरकार स्वयं भी सोशल मीडिया पर बढ़ती भारत-विरोधी सामग्री को लेकर चिंतित है और इस दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास भी गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार का मुकाबला तथ्य आधारित जानकारी साझा करके कर रहा है। इसके साथ ही दूतावास भारतीय संस्कृति, खान-पान और विविधता को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वसंत मेला जैसे लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजनों का दायरा बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि चीन में भारत की सकारात्मक छवि और मजबूत हो सके।

दोरईस्वामी ने यह भी बताया कि भारतीय पेशेवरों को रोजगार संबंधी विवादों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए दूतावास वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों का एक सहयोगी नेटवर्क तैयार कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि भारतीयों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे %ओपन हाउस% कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। वहीं, चीन के नागरिकों के लिए भारतीय वीज़ा प्रक्रिया को भी और सरल बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ सके।

दूसरी ओर, भारत में सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन की एक और पहल ने नई कूटनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। जानकारी के अनुसार, चीनी दूतावास ने भारत सरकार के समक्ष यह चिंता जताई है कि फालुन गोंग और तिब्बती समुदाय से जुड़े मीडिया संगठनों को सम्मेलन के दौरान सीमित पहुंच दी जाए। चीन नहीं चाहता कि ऐसे मीडिया संस्थानों को उसके प्रतिनिधिमंडल से सवाल पूछने या सम्मेलन के मीडिया कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिले।

हम आपको बता दें कि फालुन गोंग चीन में प्रतिबंधित आध्यात्मिक संगठन है और उससे जुड़े कई मीडिया संस्थान, जैसे %द एपॉक टाइम्स%, चीन की नीतियों के आलोचक रहे हैं। इसी तरह भारत में बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं और धर्मशाला सहित कई स्थानों से तिब्बती समुदाय के अपने मीडिया संस्थान संचालित होते हैं। भारत अब तक इन संगठनों को देश के कानूनों के दायरे में स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता रहा है। ऐसे में चीन की यह मांग केवल मीडिया प्रबंधन का मुद्दा नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी के रूप में भी देखी जा रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह यात्रा होती है तो जिनपिंग सात साल बाद भारत की धरती पर होंगे। उल्लेखनीय है कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अक्टूबर 2024 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के विवादित क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनने के बाद रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार शुरू हुआ। इसके बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की कई मुलाकातें हुईं, भारत ने चीनी नागरिकों के लिए वीज़ा फिर से जारी करना शुरू किया और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल कर दी।

बहरहाल, चीन में रह रहे भारतीयों की शिकायतें और भारत में मीडिया की पहुंच को लेकर चीन की नई मांग यह संकेत देती है कि राजनीतिक स्तर पर संवाद बढ़ने के बावजूद जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी अब भी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल सहयोग और संदेह, इन दोनों के बीच संतुलन साधने की चुनौती से गुजर रहे हैं। आने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का मंच नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भारत और चीन अपने रिश्तों को वास्तविक विश्वास और पारदर्शिता की दिशा में कितना आगे ले जा पाते हैं।

उप-चुनाव, बड़ा संकेत-भाजपा का अति आत्मविश्वास या बदलती तस्वीर

ऋतुपर्ण दवे

तीन अगस्त को तीन राज्यों के तीन नतीजे बहुत बड़े संकेत हैं। निश्चित रूप से बिहार का नतीजा जहाँ सत्ताधारी दल के लिए हैरान और परेशान करने वाला रहा। वहीं मध्यप्रदेश का नतीजा सत्ताधारी दल की अन्दरूनी गुटबाजी का परिणाम रहा। गुजरात में भाजपा की जीत स्वाभाविक कही जा सकती है। सबसे चर्चित जीत रही प्रशान्त किशोर उर्फ पीके की, क्योंकि राज्य की जनता को विकल्प के तौर पर एक नया दल जनसुराज जो मिल गया। पहले बिहार वासियों के पास दो ही विकल्प थे। राजद और भाजपा। राजद से मोहभंग हो गया था और पीके मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कवायद कर रहे थे। हालाकि बीते विधानसभा चुनाव में उनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीता और वो खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए। लेकिन बिहार की नब्ज को टटोलते रहे। इसी बीच नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली हुई जो पीके लिए मौके पर चौका लगाने जैसा रहा। हाँ, उन्होंने छक्का जरूर जड़ दिया ये बात अलग है। बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाके की है जिसे शुरू से ही भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। इस नतीजे ने न केवल यह मिथक तोड़ा बल्कि भाजपा में खलबली मचा दी। माना जा रहा है कि पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधलियों के चलते युवाओं की नाराजगी और जंतर-मंतर पर चले लंबे आन्दोलन ने भी भाजपा की छवि पर डेन्ट लगाया। इधर भाजपा अति आत्मविश्वास में थी और यह समझने में नाकाम रही कि हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती। चंदा चोरी और जेन-जी आन्दोलन के बीच भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारक उतार दिए। लेकिन राजद के चार सांसद तक बांकीपुर नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो विदेश चले गए जिन्होंने आखीर-आखीर में रोड शो किया। लेकिन तब तक बांकीपुर के मतदाताओं को यह समझना आसान हो गया कि तेजस्वी यादव और राजद अपने उम्मीदवार को लेकर गंभीर नहीं है। संकेत साफ रहा मतदाता को कहीं और शिफ्ट होना था। विकल्प के तौर पर पढ़ा लिखा, राजनीति को समझने-जानने वाले रणनीतिकार के रूप में पीके का नाम था इसलिए ज्याद सोचने-समझने के बजाए बिहार और देश के हालातों को देखते हुए मतदाताओं ने इस छोटे से चुनाव में बड़ा संदेश दे दिया। भाजपा को नुकसान पहुंचाने में भरत तिवारी एनकाउंटर मामला भी माना जा रहा है। इस एनकाउंटर ने न केवल युवाओं बल्कि खुल कर भाजपा के सवर्ण विरोधी होने को जबरदस्त हवा दी। भाजपा के तमाम जिम्मेदारों और रणनीतिकारों ने भाजपा विरोधी माहौल को थामने और बदलने की कोशिश की पर यह हो न सका। अंतत: जीत भाजपा के हाथ से निकल गई और कई दशकों से भाजपा की परंपरागत कहलाने वाली बांकीपुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कारण अतिप्रतिष्ठत हुई सीट हाथ से निकल गई। अब बिहार की राजनीति को समझने वाले यह कह रहे हैं कि पीके भाजपा सरकार, विशेषकर सम्राट चौधरी के लिए सदन के अन्दर भी और बाहर भी मुश्किलें बढ़ाएंगे क्योंकि ब उनका मकसद सिर्फ विधायकी नहीं बल्कि अपनी पार्टी को बिहार में नया मुकाम जो देना है। कमोवेश यही स्थिति मध्यप्रदेश के दतिया में रही। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया से नरोत्तम मिश्रा की हार के बाद भाजपा के अन्दरूनी हलकों में कहीं खुशी, कहीं गम का माहौल था। लेकिन वहां से चुने गए कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा हो जाने के बाद अप्रैल में अयोग्य घोषित कर दिए जाने से हुए उपचुनाव में घनश्याम सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर सीट को बरकरार रखा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बिना चुनाव लड़े मुश्किल नरोत्तम मिश्रा की हुई।

शादी में बारिश का होना कैसा शगुन होता है

मौसम कैसा होगा-सबको चिंता होती है कि कहीं बारिश आफत ना बन जाये। लोगों को चिंता रहती है उस दिन मौसम खराब या अप्रत्याशित ना हो जाये इसलिए लोग भावी मौसम की भविष्यवाणी जानते रहते हैं।

शादी है खुशी का दिन-आपकी शादी का दिन आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन होना चाहिए। यह दिन प्यार, खुशी, आशा, उम्मीद, और उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए।

बारिश फलदायी है-बारिश से सूखे स्थानों को पानी मिलता है, फसलें लहलहाती हैं, इस प्रकार बारिश फलदायी है और इसे अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे ध्यान रखते हुये शादी के दिन होने वाली बारिश को अच्छी किस्मत की निशानी माना जाता है।

बारिश कई अच्छी चीजों की प्रतीक है-आपके जीवन के इस खास दिन पर होने वाली बारिश को कई कारणों से अच्छे भाग्य की निशानी माना जाता है। बारिश आशीर्वाद, सफाई, एकता, और एक नई शुरुआत की प्रतीक है।

कुछ संस्कृतियों में इसे परिवार के बढने की प्रतीक भी माना जाता है। इन सभी सकारात्मक कारणों से शादी के दिन होने वाली बारिश को अच्छा शगुन माना जाता है। आपका क्या मानना है।

आशा और आशीर्वाद-बारिश आशीर्वाद की प्रतीक है, और हर कोई अपनी शादी में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। आशीर्वाद आशा और समर्थन का सूचक है। जब आप एक नई संभावनाओं के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हों तो आपको आशावादी जरूर होना चाहिए।

समृद्धि-आशीर्वाद, शारीरिक और भौतिक दोनों अर्थों में समृद्धि का प्रतीक है।

एक खुशहाल जीवन की आशा में, शादी के दिन होने वाली बारिश को अच्छे भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

नई शुरुआत-बारिश के बाद हर चीज साफ हो जाती है और हर चीज तरोताजा एवं नई नजर आती है। जो लोग शादी करने करने जा रहे हैं वो भी नए सपने बुनते हुये एक साथ एक नई जिंदगी बसर करने जा रहे हैं। बारिश एक नई शुरुआत की सूचक है।

परिवार के बढने का संकेत-इसके साथ ही बारिश परिवार के बढने का संकेत है। पानी से चीजें उगती और बढती हैं। लोगों को उम्मीद होती है शादी के बाद उन्हें बच्चों की प्राप्ति होगी। इसलिए कुछ संस्कृतियों में माना जाता है बारिश नवयुगल के बच्चे पैदा होने और परिवार बढने का संकेत है, इसलिए यह एक प्रकार का आशीर्वाद है।

भौतिक संपत्ति-चीजों में वृद्धि होने तात्पर्य भौतिक धन-धान्य से है इसलिए यह प्रचुर मात्रा में संसाधनों, उत्पादकता, और एक अच्छी फसल आदि का प्रतीक है।

एकता-शादी के दिन बारिश होने को एकता का सूचक भी मान सकते हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि शादी वाले आपस में गठजोड़ करते हैं यानि कि ''गाँठ बांधते हैं।''

भारतीय महिलाएं क्यूं लेती हैं अपने सिर पर घूंघट

हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा समाजिक परंपराओं को निभाते और मानते हुए देखा गया है, जैसे कि वे हमेशा ही पारंपरिक कपडे, और गहने, पहनती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं और सर पर घूंघट लेती हैं। भारत में महिलाओं द्वारा सिर को ढकने की प्रथा ने हमेशा ही हमारे अंदर जिज्ञासा बढाई है, खासतौर पर उन लोगों के लिये जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग हैं। हिंदू परंपराओं के पीछे छुपे विज्ञान को समझना है जरुरी सिर पर घूँघट डालना अपने से बडों के सम्मान के रूप में देखा गया है, इसलिए महिलाएं अपनों से बडों के सामने अक्सर घूँघट करती हैं। शहरों में यह कुछ कम देखने को मिलता है मगर गांवों में आज भी महिलाएं अपने सर, चेहरा और गर्दन को पुरुषों से ढांक के रखती हैं।

भारतीय महिलाएं घूँघट क्यों लेती हैं।

क्या कहता है हिंदू ग्रंथ: आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हिन्दू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पर्दे में रहने का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि पूजा के समय भी सर पर घूँघट रखना जरूरी नहीं है। भारतीय महिलाएं क्यूं पहनती हैं नोज रिंग सुरक्षा के कारण: कुछ धर्मों में पर्दा रखना इसलिए जरुरी है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर महिलाएं खुद को पर्दे में रखेंगी तो वे अन्य पुरुषों से सुरक्षित रहेंगी। महिलाएं केवल अपने पति या पिता के सामने बेपर्दा हो सकती हैं।

मुस्लिम का आक्रमण: महिलाओं को पर्दे में रखने का रिवाज मुस्लिम शासन के बाद से हुआ है। भारत में राजपूत शासन के दौरान महिलाओं को आक्रमणकारियों के बुरे इरादों से बचाने के लिए उन्हें पर्दा में रखा जाता था। इसका सबसे बडा उदहारण हैं चित्तौड की रानी पद्मिनीजिनकी खूबसूरती को देख कर अल उद दीन खिलजी ने उन्हें पाने के लिए चित्तौड पर आक्रमण कर था। लेकिन रानी पद्मिनी ने जौहर का प्रदर्शन किया और दुश्मन के चंगुल से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। तब से भारत में महिलाओं को पर्दे में रखने का रिवाज शुरू हो गया। घूँघट का अस्तित्व मध्यकालीन के बाद से आया है, उस वक्त इसकी आवश्कता थी लेकिन समय के साथ इसे महिलाओं के ऊपर थोपा जाने लगा।

क्या हैं यमराज द्वारा बताये मृत्यु रहस्य

हम सभी जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं और एक दिन हमें मरना है। काल की घडी में धनी राज या भिखारी का एक ही स्थान है। जब भी मृत्यु का विषय आता है, चर्चा काफी रोचक हो जाती है क्योकि सभी मृत्यु के बारे में और जानना चाहते हैं। लोग मृत्यु के बारे में सब कुछ जानने के लिये जिज्ञासु हो जाते हैं। जो लोग ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं वो सही जगह पर आये हैं क्योकि बोल्डस्की मृत्यु के देवता यमराज द्वारा मृत्यु के बारे में बताये गये कुछ छिपे रहस्यों को उजागर कर रहा है। प्रचीन धर्मग्रन्थों के अनुसार मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में यमराज और नचिकेत नामक बालक के बीच चर्चा हुई थी। क्या है हिन्दु धर्म में मृत्यु का संकेत यहाँ पर कुछ रहस्यों को उजागर किया जा रहा है जिन्हें मृत्यु के देवता यमराज द्वारा नचिकेत को बताया गया था।

नचिकेत के वरदान-

जब नचिकेत यमराज से मिलने गये तो उन्हों ने तीन वरदान माँगे। पहले वरदान में पिता के प्रेम की कामना, दूसरे में अग्नि विद्या का ज्ञान और तीसरे में मृत्यु और आत्मा का ज्ञान माँगा। यमराज अन्तिम वरदान को नहीं पूरा करना चाहते थे लेकिन बालक ने हठ किया। इसलिये यमराज मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके रहस्योद्घाटन के लिये तैयार हो गये।

रहस्योद्घाटन -

धर्मग्रन्थों के अनुसार यमराज ने बताया कि ओउम (ओंकार) परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य के हृदय में ब्रहमा का वास होता है।

आत्मा -

यमराज ने कहा कि आत्मा मनुष्य की मृत्यु के बाद भी नहीं मरती। संक्षेप में, शरीर का आत्मा के विनाश से कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती न मरती है।

ब्रहमरूप -

मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म-मत्यु के चक्र को पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जन्म-मत्यु के चक्र अर्थात ब्रहम रूप से मुक्त हो जाता है।

ईश्वरीय शक्ति -

यमराज ने कहा कि जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते और नास्तिक होते हैं वे मृत्यु के बाद भी शान्ति की तलाश में रहते है। उनकी आत्मायें भी शान्ति की तलाश करती है।

महर्षि श्रृंगी : भारतीय संस्कृति, वैदिक परम्परा और सिखवाल समाज की अमूल्य धरोहर

भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने अपने इतिहास और संस्कृति का आधार केवल राजाओं और युद्धों को नहीं बनाया, बल्कि उन ऋषियों को सर्वोच्च स्थान दिया जिन्होंने तप, त्याग, ज्ञान और धर्म के माध्यम से समाज को दिशा प्रदान की। ऐसे ही महान ऋषियों में महर्षि ऋष्यशृंग (महर्षि श्रृंगी) का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है।

आज विडंबना यह है कि भगवान श्रीराम के जन्म की कथा से अधिकांश लोग परिचित हैं, किंतु उस पुत्रेष्टि यज्ञ के महर्षि, जिनके वेदज्ञान, तपबल और यज्ञीय सामर्थ्य से यह दिव्य कार्य संपन्न हुआ, उनके बारे में अपेक्षाकृत बहुत कम लोग जानते हैं। महर्षि श्रृंगी भारतीय ऋषि परम्परा के ऐसे तेजस्वी नक्षत्र हैं, जिनका योगदान केवल धार्मिक आख्यानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और वैदिक परम्परा की आधारशिला से भी जुड़ा हुआ है।

पौराणिक परम्पराओं के अनुसार महर्षि श्रृंगी, महर्षि विभाण्डक के पुत्र थे। उनका जीवन वन की निर्मलता, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या का अनुपम उदाहरण रहा। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों में उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अंगदेश में भीषण अकाल के समय उनके आगमन से वर्षा होना तथा वृष्टि यज्ञ के माध्यम से जनजीवन को पुनर्जीवित करना इस तथ्य का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति में ऋषियों को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि लोककल्याण का वाहक भी माना गया है।

महर्षि श्रृंगी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण

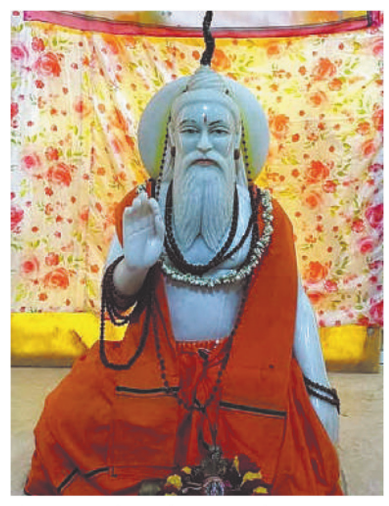

योगदान अयोध्या में सम्पन्न पुत्रेष्टि यज्ञ माना जाता है। गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर उन्होंने महाराज दशरथ के लिए इस महायज्ञ का अनुष्ठान कराया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। इस दृष्टि से महर्षि श्रृंगी केवल रामायण के एक पात्र नहीं, बल्कि स्वयं श्रीराम के अवतरण की कथा के प्रमुख सूत्रधार हैं। राजकुमारी शांता के साथ उनका विवाह उन्हें अयोध्या के राजवंश से भी जोड़ता है।

सिखवाल, श्रृंगवाल अथवा सुखवाल ब्राह्मण समाज स्वयं को महर्षि श्रृंगी की वैदिक परम्परा का उत्तराधिकारी मानता है। यह केवल वंश परम्परा का विषय नहीं, बल्कि संस्कारों, वेदाध्ययन, यज्ञीय परम्परा तथा सामाजिक मर्यादाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखने का दायित्व भी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा देश के अन्य राज्यों में फैला यह समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक परम्पराओं को जीवित रखने का सतत प्रयास कर रहा है।

हालाँकि इतिहास और पुराणों से संबंधित अनेक कथाओं के विभिन्न संस्करण भी उपलब्ध हैं। इसलिए आवश्यक है कि समाज भावनाओं के साथ-साथ प्रमाणिक ग्रंथों, शोध एवं ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अपने गौरवशाली अतीत का अध्ययन करे। तथ्य जितने अधिक प्रमाणित होंगे, हमारी समृद्ध विरासत उतनी ही सशक्त रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुँच सकेगी।

आज आवश्यकता केवल महर्षि श्रृंगी की जयंती मनाने या उनके नाम का स्मरण करने की नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की है। तप का अर्थ आत्मसंयम, ज्ञान का अर्थ विवेक, यज्ञ का अर्थ लोककल्याण और पवित्रता का अर्थ चरित्र निर्माण है। यदि समाज इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाए, तभी महर्षि श्रृंगी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी।

महर्षि श्रृंगी केवल एक पौराणिक ऋषि नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परम्परा के ऐसे शिखर पुरुष हैं, जिनकी विरासत आज भी समाज को संस्कार, संयम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनके जीवन का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों वर्ष पूर्व था। भारतीय संस्कृति की इस महान धरोहर को समझना, संरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना हम सभी का नैतिक दायित्व है।

- सुरेश कुमार व्यास जानम

दुनिया में हर चीज है नश्वर

दुनिया में हर काम में लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें समझ नहीं रहती है बल्कि वो उस तक अक्षम्य होते जाते हैं, उस काम को करने में, उस काम को उस तरीके से समझने में, उसकी आधुनिकता को समझने में। अगर आप भी किसी काम को बखूबी करने के बाद अचानक से उसमें गिरावट महसूस करते हैं तो समझें कि शायद आपको उसमें भी कुछ नयापन लाने की जरूरत है या फिर आपको उस काम सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। दुनिया में जो भी निर्मित है, जिसका भी निर्माण किया गया है, सभी में अध्यात्म का सार होता है, सभी के जीवन का एक चक्र होता है। एक सम्पूर्ण जीवन के बाद उसे खींचना या जबरन इस्तेमाल करना या चलाना सिर्फ मनुष्य की जिद होती है।

सम्पूर्णता होने के बाद संभावनाओं के बारे में सोचना गलत नहीं है लेकिन उसे पाना गलत है। दुनिया में हजारों लोग इस भंवर में फसे रह जाते है, उन्हे समझ नहीं आता है कि यर्थाथ क्या है,सत्य क्या है। कई बार तो वे सत्य जानते हुए भी दूर भागते हैं। खुद को मूर्ख बनाने से बेहतर है कि आपका जीवन के प्रति उठाया गया हर कदम सटीक और भावपूर्ण हों, उसमें कोई आशा और निराशा न हों। शरीर से परे भी दुनिया में पाने को बहुत कुछ है, खुद को समझें, अपने आप को समझें, अपनी सोच को समझें, जो देखा है, दिखा हुआ है, समझा हुआ है, उसे समझकर क्या करना। जो इंसान शरीर को समझता है, उसे लगता है दुनिया में शरीर ही सबकुछ है, उसे बुढापे से डर लगता है, क्योंकि उसे अनुभव से प्यार नहीं होता है। शरीर का बूढा होना समस्या नहीं है, यह तो आर्शीवाद है लेकिन हम इससे ही कतराते हैं क्योंकि हम दुर्बल हो जाते हैं। मछली-जब एक बार आप जीवन में उच्च शिखर पर पहुंच जाते है, तो आपको अपने जीवन की दिशा और ऊर्जा को सही करने का मौका मिलता है, बस उस बिंदु को जिसने समझा वह सच्चा व्यक्ति है। सफलता और सच्चाई में रत्ती भर भी अंतर नहीं है दोनों ही पूरक हैं। लडकी-हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन से उसके मरने की स्पीड क्लॉक चलने लगती है, कोई भी नश्वर नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे विश्लेषणकर्ता है तो आपको कई बार इसका आभास भी हो जाएगा। अगर आप इन बातों को मजाक मानते हुए शरीर को ही सबकुछ मान लेते हैं तो स्वयं को मूर्ख बनाते हैं। पत्थर-बढती उम्र सिर्फइतना ही नहीं है कि आपका शरीर कांपने लगा है, इसे आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं।

आपने इतनी उम्र बिताई, हजारों यादें लोगों को दी और उन्हे प्रेरणा दी, सहारा दिया, प्यार दिया, अच्छे पल दिए , इसलिए जब आखिरी सांसे लें तो मुस्कराएं और सोचे कि जो भी वक्त बिताया वो बेहतरीन था। इस सोच की कमी हमारी गलती नहीं हैं बल्कि हमारी पारंपरिक सोच का नतीजा है, हमारा हर तरीके से न सोचने का परिणाम है। कई बार तो जिंदगी के बुरे अनुभव भी लोग एक-दूसरे के साथ साझा नहीं करते हैं उन्हे लगता है कि इससे बदनामी होगा, उन्हे शायद यह नहीं मालूम होता है कि न अनुभवों से किसी को राह मिल सकती है, किसी को सबक मिल सकता है। पर नही हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। हमें अमरता चाहिए, हम डरते हैं कि हम नश्वर है, पर सच ये है कि दुनिया में हर क्षण, हर दिल, हर वस्तु, प्राणी सब कुछ नश्वर है। नाश सभी का होता है पर अनुभव उसे जीवित रखता है। जीवन में मृत्यु में फर्क नहीं होता है, फर्क सोच में होता है।

मां पार्वती के जल से गणेश का अभिषेक

बुधवार को अच्छी बारिश की कामना को लेकर हजारों महिला-पुरुष पार्वती नदी का जल लेकर चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान का जल से अभिषेक किया। उसके बाद विधि विधान से पूजा-अर्चना कर अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की। ज्ञात हो कि हर वर्ष अषाढ के माह में ग्राम पार्वती लोग पार्पती नदी में से जल भरकर व झंडा लेकर हजारों की तादात में पैदल जत्थे के रूप में सीहोर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान रास्ते में पडने वाले दर्जनों गांव के लोग उनका स्वागत कर उनके साथ जत्थे में शामिल हो जाते हैं। यह जत्था पार्वती से शुरू होता है, जिसमें पिपलिया नगर, बाबडिया, खजूरी, मूंडला, कराडिया, बक्तल, जगनीखेडी, बिजोरा, बिजोरी, नयापुरा, पीलीखेडी, कोडिया, महोडिया सहित दर्जनों ग्राम के लोग शामिल होते हुए चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचते हैं। जहां पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का अयोजन किया जाता है। यह परम्परा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें सभी ग्रामीण बडे सद्भाव और सोहाद्र के साथ हिस्सा लेते हैं, जिसमें बच्चे-बूढे, महिला-पुरष सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं।

इस पर्वत पर गिरा था देवी सती का सिर

चंबा-मसूरी मोटर मार्ग पर तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर सुरकुट पर्वत पर सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर स्थित है। मान्यता है कि देवी सती का सिर इस पर्वत पर गिरा था। गंगा दशहरे के मौके पर यहां मेला लगता है, जबकि हर साल नवरात्रि में मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया तो उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव के मना करने पर भी देवी सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। वहां भगवान शिव का अपमान होने पर वे यज्ञ में कूद गई। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वह क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यहां सती की देह को त्रिशूल में लटकाकर सृष्टि में विचरण करने लगे। इस दौरान सुरकुट पर्वत पर सती का सिर गिरा जिस कारण इसका नाम सुरकंडा पडा। तभी से यह स्थान सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर इकलौता सिद्धपीठ है, जहां गंगा दशहरे के मौके पर मेला लगता है और हर साल नवरात्रि में मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। खास बात यह है कि मंदिर में प्रसाद के रूप में रौंसली (थुनेर) के पत्ते दिए जाते हैं। दूर-दूर से लोग इस सिद्धपीठ के दर्शनों के लिए यहां आते हैं।

बुद्ध संसार के हर प्राणी से इतना प्रेम करते थे

भगवान बुद्ध एक बार उपदेश देने एक गांव में पहुंचे। वहां उनके पडाव का अंतिम दिन था। तब वह उस गांव के एक व्यक्ति के यहां पहुंचे। वो गरीब था। उसके पास भगवान बुद्ध के आतिथ्य के लिए कुछ भी न था। तब उसने घर के बाहर देखा। जहां उसकी नजर बरसात में भीगी लकडियों पर पडी, जिन पर कुकुरमुत्ता(मशरूम) लगे हुए थे। उसने उन्हें तोडा और बडे ही प्रेमपूर्वक उनकी सब्जी बनाई। लेकिन उस गरीब को पता नहीं था की मशरूम काफी कडवे जहर के समान थे। वह बुद्ध से पूछता कि कैसा है भोजन और बुद्ध कहते बहुत ही स्वादिष्ट। मशरूम जहरीले थे। जिसके कारण उसका जहर बुद्ध के शरीर में फैल गया। यह देख उस व्यक्ति ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बुद्ध से कहा, कि जब आपको मशरूम कडवे लगे तब आपने उस व्यक्ति से क्यों नहीं कहा।

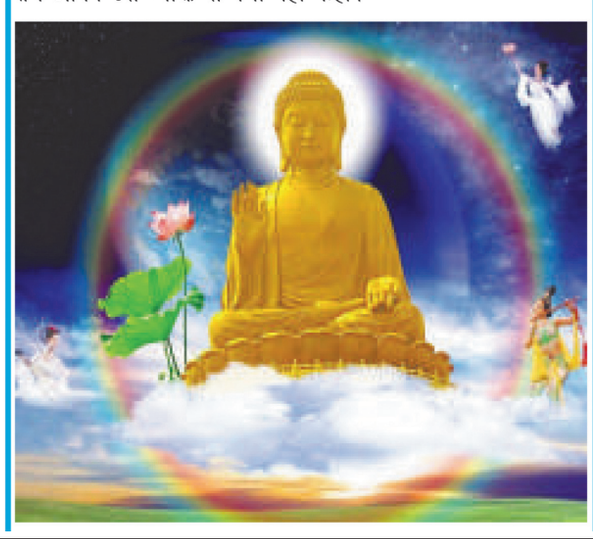

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

चाहे जो हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी: हसीना

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मीडिया से वर्चुअल बातचीत में कहा कि मैं उस व्यक्ति के रूप में बोल रही हूं जिसने अपना जीवन बांग्लादेश के लोगों के साथ बिताया और मुझे मेरे देश से दूर कर दिया गया, लेकिन मैं अपने लोगों से कभी अलग नहीं हुई। उन्होंने दो साल पहले हुए हिंसक प्रदर्शनों की निंदा की।मीडिया को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि पिछले दो सालों में मैंने अपने प्यारे बांग्लादेश को पीड़ित होते हुए देखा है। यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिसे हमने बनाया था, यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं जुलाई और अगस्त 2024 के बारे में सच्चाई बताती हूं। यह शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था। मेरी सरकार ने शरू से बातचीत, कानूनी प्रक्रिया और धैर्य के माध्यम से इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश की, लेकिन सुधार की भाषा के पीछे, संगठित समूह छात्रों की मांग को हिंसक राजनितिक हथियार में बदलने के लिए काम कर रहे थे।

तृषा पर अभद्र टिप्पणी से घिरे उदयनिधि

नई दिल्ली। तमिलनाडु में ष्ठस्ख्य नेता उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. आरोप है कि कावेरी जल मामले पर बोलते हुए उन्होंने अपने भाषण में एक्ट्रेस तृषा को लेकर भद्दी टिप्पणी की, जिसके बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. उनके बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देर शाम तंजावुर के सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से जमानत मिल गई. उनके खिलाफ पुलिस ने छह धाराओं में मामला दर्ज किया है. वहीं, पुलिस पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में थाने के बाहर एकत्र हुए डीएमके कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और धक्का-मुक्की के दौरान कुछ समर्थक घायल हो गए. पुलिस ने थाने के बाहर पहुंचे डीएमके समर्थकों को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए तमिलनाडु के लिए कावेरी जल के उचित प्रबंधन को लेकर सरकार की आलोचना की।

बंगाल से जा चुके हैं 1 लाख बांग्लादेशी

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम तेज हो गया है. राज्य सरकार ने फेंसिंग के लिए अधिग्रहित जमीन का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा गृह मंत्रालय को सौंप दिया है. इस बीच दावा किया गया है कि सीमा पर सख्ती बढ़ने के बाद एक लाख से ज्यादा बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुके हैं. वहीं, एसआईआर प्रक्रिया में दोबारा आवेदन नहीं करने वाले करीब 20 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है. इन सबके अलावा यह भी दावा किया गया है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एनसीपीआई के सभी 20 सांसदों के साथ बंग भवन में दोपहर का भोजन किया. राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए अधिग्रहित जमीन का करीब 80 फीसदी हिस्सा गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है. इस जमीन के मिलने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा के कई हिस्सों में फेंसिंग का काम आगे बढ़ रहा है इससे पहले 22 जुलाई राज्य सरकार ने बीएसएफ को करीब 1,024.75 एकड़ जमीन सौंपने की जानकारी दी थी।

डाबर को शहद-घी बेचने पर रोक

नईदिल्ली। आजकल आप दुकान या ग्रोसरी स्टोर पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता होगा है कि खाने का कोई पैकेट आपने सिर्फ इसलिए खरीद लिया होगा क्योंकि उस पर बड़े अक्षरों में लिखा 100% प्योर, 100% नेचुरल , लिखा था. ऐसे शब्द मन में भरोसा पैदा करते हैं कि यह सब लिखा है तो सच ही होगा. उसपर आप अगर स्नस्ख्ड्ड की मुहर देख लेते होंगे तो फिर पैकेट खरीद ही लेते होंगे कि मुहर लगी है तो 100 शुद्ध वाली बात ठीक ही होगी, लेकिन हाल ही में स्नस्ख्ड्ड ने डाबर इंडिया को शहद, घी और तेल समेत कुछ फूड प्रोडक्ट पर 100% जैसे दावों को लेकर नोटिस भेजा है. साथ ही 100 प्रतिशत के दावे के साथ इन चीजों को बेचने पर रोक लगा दी है.इसके बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि आखिर किसी भी खाने की चीज पर लिखे ऐसे दावे कितने सच होते हैं? क्या इन दावों की सच्चाई के लिए कोई मेडिकल टेस्ट होते हैं।

ईओ हत्याकांड पर तेजस्वी का विधायक पर आरोप

पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या का मामला उठाया है. उन्होंने दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मांग की है. तेजस्वी यादव ने रविवार को मृतक विमल कुमार के परिजनों से मुलाकात की थी. तेजस्वी ने सम्राट चौधरी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दूसरे सरकारी अधिकारी की हत्या हुई है. उनका दावा है कि इस सरकार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की. तेजस्वी ने बताया कि विमल कुमार के दो छोटे बच्चे और पत्नी हैं. वे सभी शोक में हैं. तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक सोनू सिंह पर आरोप लगाते हुए उन्हें इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है. मृतक ईओ विमल कुमार की पत्नी ने भी बीते दिन गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, %मेरे पति को डेहरी विधायक ने जान से मरवाया है।

जम्मू-कश्मीर को मिले संवैधानिक अधिकार

अनुच्छेद 370 हटने से हुआ चौतरफा विकास : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सात साल पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। 5 अगस्त, 2019 को हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में काफी प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में बांट दिया गया।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(ए) इतिहास बन गए थे, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के संविधान के ज़रिए महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया गया, जिन्हें दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्होंने कहा कि तब से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढाँचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएँ हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, वे भारत के संविधान के पूरी तरह से लागू होने की वजह से सशक्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले को रद्द करने की सातवीं सालगिरह, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के साथ पड़ रही है। राष्ट्रीय एकता का उनका सपना 5 अगस्त 2019 को सच हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने दशकों पहले जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से सच हो गया।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार के संकल्प को भी दोहराया और वादा किया कि हर नागरिक को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का मौका मिले।

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मां भारती का मस्तक सदा ऊंचा रहे। 5 अगस्त, 2019 भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ एक विधान-एक निशान-एक प्रधान के स्वप्न तथा एक भारत-श्रेष्ठ भारत के राष्ट्रीय संकल्प को ऐतिहासिक सिद्धि मिली।

उन्होंने कहा, यह निर्णय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस राष्ट्रनिष्ठ स्वप्न की पूर्णता थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया। बीते सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर ने आतंकवाद से शांति, अलगाववाद से एकात्मता और अस्थिरता से विकास की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। आज यह प्रदेश नए भारत की आकांक्षाओं, प्रगति और समृद्धि का सशक्त प्रतीक बन चुका है। राष्ट्र प्रथम की भावना से ओत-प्रोत इस युगांतरकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का हार्दिक आभार व अभिनंदन।

जम्मू-कश्मीर के अधिकार और पहचान लौटाकर रहेंगे : उमर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन प्रशासनिक और संवैधानिक बदलावों को पलटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने इस क्षेत्र के विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया था और इसकी अनूठी पहचान को खतरे में डाल दिया था। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और पूर्व राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में बांट दिया गया।

इस फ़ैसले की सातवीं बरसी पर, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता 'स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग' की कुछ लाइनें लिखीं।

उन्होंने कहा कि 7 साल हो गए, न तो हम भूले हैं और न ही हमने समझौता किया है, और मौजूदा हालात को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। मैं और मेरी पार्टी जम्मू-कश्मीर के साथ जो कुछ भी किया गया—जिससे हमारे अधिकार छिन गए और हमारी पहचान पर खतरा पैदा हुआ—उसे पलटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'जंगल सुंदर, घने और गहरे हैं। लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं। और सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है'

संसद परिसर में विपक्ष का विरोध मार्च

कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा- अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे?

नईदिल्ली। बुधवार को विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। उन्होंने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान, राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ियों पर चर्चा और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और प्लेकार्ड भी उठाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और संसद से शाह की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए मांग की कि वे विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बात करें। खड़गे ने पत्रकारों से कहा कि वे सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? वे संसद का अपमान कर रहे हैं। कई दिन हो गए हैं, लेकिन वे सदन में नहीं आना चाहते। आकर बयान देने में क्या दिक्कत है? विरोध कर रहे सांसदों ने मांग की कि शाह संसद के दोनों सदनों में पिछले महीने पेपर लीक मामले से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती पर बयान दें।

विपक्ष के कई सदस्यों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए दान के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। जम्मू-कश्मीर के सांसदों ने केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की; यह विरोध प्रदर्शन अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सातवीं बरसी के मौके पर हुआ। सांसदों ने अमित शाह जवाब दो जैसे नारे लगाए और सरकार की आलोचना करते हुए पोस्टर दिखाए। मंदिर के दान के कथित दुरुपयोग के खिलाफ़ सांकेतिक विरोध के तौर पर उन्होंने मकर द्वार की सीढ़ियों के पास दान-पात्र भी रखे, और कुछ सांसदों ने उनमें नकद पैसे भी डाले।

इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के कई नेता शामिल हुए, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव, टीएमसी नेता सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा, एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले, जेएमएम की महुआ माजी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन शामिल थे।

रिजिजू-राहुल मुलाकात, संसद गतिरोध खत्म होने की उम्मीद?

संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ लगभग 50 मिनट तक बैठक की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में मौजूद थीं और उन्होंने बातचीत में हिस्सा लिया। यह बैठक संसद परिसर में राहुल गांधी के कार्यालय में हुई। बैठक के बाद रिजिजू ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और उम्मीद जताई कि संसद में जारी गतिरोध जल्द ही सुलझ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने रिजिजू से कहा कि विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफ़ा नहीं मांग रहा है। इसके बजाय, वे चाहते हैं कि शाह गतिरोध की मुख्य वजह बने मुद्दे पर संसद में बयान दें। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री को सदन को संबोधित करना होगा। सूत्रों ने बताया कि बाद में रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। सूत्रों के मुताबिक, रिजिजू ने राहुल गांधी से अहम कानूनों पर उनकी राय मांगी, जिनमें प्रस्तावित परिसीमन बिल और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) से जुड़े संशोधन शामिल हैं। सरकार इन लंबित बिलों पर कांग्रेस पार्टी का रुख जानना चाहती थी। इस बैठक को सरकार और कांग्रेस के बीच भरोसा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में!

नईदिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख अजीत अगरकर का कार्यकाल एक महीने में खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक, बोर्ड के बड़े अधिकारी उनकी जगह बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के मौजूदा प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को लाने की योजना बना रहे हैं। अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म होने वाला था, लेकिन बोर्ड ने उन्हें तीन महीने का एक्सटेंशन दिया था। उम्मीद थी कि पूर्व तेज़ गेंदबाज़ को एक और एक्सटेंशन मिलेगा, जिससे वे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के खत्म होने तक इस पद पर बने रहेंगे।

हालांकि, पिछले कुछ महीनों में हालात पेचीदा हो गए हैं, खासकर भारत की वनडे टीम में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही उठापटक की वजह से। ऐसी खबरें थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ रोहित की आखिरी सीरीज़ होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट से रोहित को बाद के असाइनमेंट्स से बाहर रखने के बारे में बात भी की थी।

लेकिन, एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब यह खबर सामने आई कि लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला तीसरा वनडे रोहित का आखिरी मैच होगा। उस आखिरी मैच में हिटमैन ने शानदार शतक जड़ दिया, जिससे सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट, दोनों ही बैकफुट पर आ गए। तीसरे वनडे से पहले जानकारी लीक होने के कुछ ही समय बाद, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी एक बयान जारी किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह बयान मुख्य चयनकर्ता अगरकर से बात किए बिना ही दिया। उन्होंने कहा कि जब तक रोहित टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं, तब तक वह खेलते रहेंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा निफ्टी 24,624 पर हुआ बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। निवेशकों ने राहत की सांस ली क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखा और अपनी न्यूट्रल नीति को भी बरकरार रखा। कारोबार के अंत में निफ्टी50 9.75 अंक यानी 0.04 फीसदी की बढ़त के साथ 24,624.65 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 152.05 अंक यानी 0.19 फीसदी चढ़कर 78,581.00 के स्तर पर बंद हुआ। मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन सकारात्मक रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.08 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.69 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली।

आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान मामूली बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी मामूली घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल का घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर भी कुछ असर पड़ सकता है। आरबीआई ने जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6 प्रतिशत और मुद्रास्फीति का अनुमान 5.1 प्रतिशत रखा था। केंद्रीय बैंक के अनुसार, हालांकि अब तक महंगाई का सामान्य दबाव कम बना हुआ है।

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, 80 डॉलर से नीचे ब्रेंट

नईदिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की कोशिशों में प्रगति की खबरों के बाद बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड दोनों करीब तीन हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर आ गए। ब्रेंट क्रूड लगभग 5 फीसदी टूटकर 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। दोनों बेंचमार्क 13 जुलाई के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार करते दिखे। मौजूदा कारोबार में ब्रेंट करीब 78.31 डॉलर और डब्ल्यूटीआई 74.42 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो सकती है।

रीपो रेट 5.25% पर बरकरार न्यूट्रल रुख कायम

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अगस्त 2026 की समीक्षा बैठक में रीपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने रीपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखने का फैसला लिया। इसके साथ ही एमपीसी ने 'न्यूट्रल' मौद्रिक नीति रुख भी बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से रीपो रेट को यथावत रखने का समर्थन किया। तीन से पांच अगस्त तक चली इस बैठक में घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालात, महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय बाजारों की स्थिति की समीक्षा की गई। रीपो रेट के साथ-साथ आरबीआई ने अन्य प्रमुख नीतिगत दरों को भी अपरिवर्तित रखा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।

रोजगार, संपत्ति, एआई और बढ़ती असमानता तय करेंगे भारत का अगला दशक

शंकर अय्यर

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था कई तरह के बदलावों से गुजर रही है। यहां एक साथ कई बदलाव हो रहे हैं-सत्ता बदल रही है, संपत्ति बनाने का तरीका और कमाई करने वाले लोग भी बदल रहे हैं। आने वाला दशक किसी एक ट्रेंड से नहीं, बल्कि इन सभी बदलावों को मिलाकर पड़ने वाले असर से तय होगा। यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भी साफ झलकता है, जहां राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करदाताओं के पैसे से मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। संपत्ति वालों के लिए यह सबसे अच्छा समय है, पर, इन बदलावों के बीच फंसे हुए लोगों के लिए यह मुश्किल दौर है।

भारत में एकसाथ पांच बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला, पारिवारिक कारोबारों में नियंत्रण व संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित हो रही है। दूसरा, बिजनेस मॉडल वितरण से हटकर प्लेटफॉर्म आधारित होते जा रहे हैं। इससे यह तय हो रहा है कि काम का फायदा किसे मिलेगा। तीसरा, बिजनेस का एक 'टोल-बूथ मॉडल' उभर रहा है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, वेलनेस कोचिंग और पर्यटन, जो लोगों की बचत के दम पर फल-फूल रहा है। चौथा, बढ़ती कीमतों के कारण खपत 'के-शेप' में बंट रही है, इसलिए सरकारों को कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाना पड़ रहा है। पांचवां, एआई उस क्षेत्र से इन्सानी दखल कम कर रहा है, जिसने दो दशकों में बड़ी संख्या में स्नातकों को रोजगार दिया था। इनमें से कुछ भी अचानक या विरोधाभासी नहीं है।

जीडीपी के नजरिये से देखें, तो भारत मजबूत स्थिति में है और तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पर, रोजगार, मालिकाना हक या खपत की दृष्टि से देखने पर 'के-शेप्ड' अर्थव्यवस्था दिखाई

देती है, जिसमें फायदों का वितरण असमान है। अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) व जूलियस बेयर का मानना है कि भारत एक अभूतपूर्व पीढ़ी-दर-पीढ़ी संपत्ति हस्तांतरण के दौर से गुजर रहा है। अगले दशक में करीब 15 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होने का अनुमान है।

अर्थशास्त्री जोसेफ शुमपीटर ने बड़े बदलाव या मौजूदा मॉडल को पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया को 'क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन' (रचनात्मक विनाश) कहा था। अब कंपनियां कारखाने, गोदाम और नई शाखाएं खोलने के बजाय अपने नेटवर्क का विस्तार करके तेजी से बढ़ रही हैं। उनकी सफलता बाजार में उनके मूल्यांकन में दिखाई देती है। इसका गणित समझिए। खाद्य सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म 'एटरनल' का मूल्य देश की प्रमुख पैकेज्ड फूड कंपनी नेस्ले के बराबर है। लगातार घाटे में चल रही स्विगी का मार्केट कैप करीब 78,600 करोड़ रुपये है और शेयर बाजार में कई ब्रोकर इसे 'खरीदने लायक शेयर' मानते हैं। इसी तरह, एचडीएफसी बैंक के 4,175 शहरों में 9,689 शाखाएं और 2.11 लाख कर्मचारी हैं। इसके बावजूद, निवेशक बैंक की कमाई का करीब 14 गुना मूल्य देने को तैयार हैं। वहीं, इसकी सहयोगी एचडीएफसी एएमसी, जिसमें केवल 1,738 कर्मचारी हैं, उसके लिए निवेशक कमाई का 38 गुना मूल्य चुकाने को तैयार हैं। यह दिखाता है कि आज निवेशक कम कर्मचारियों और कम संपत्ति के साथ ज्यादा मुनाफा कमाने वाले कारोबारों को तवज्जो दे रहे हैं। भारतीय रिटेल निवेशकों के बढ़ते भरोसे के पीछे भी यही बड़ी वजह है।

मध्यम वर्ग पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़ती जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में, अपनी बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसके पास शेयर बाजार और इक्विटी निवेश का सहारा लेने के अलावा बहुत कम विकल्प बचे हैं। यही कारण है कि साल के पहले छह महीनों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों ने फंड्स के जरिये 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। इसी कारण एसेट मैनेजर और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां चर्चा में हैं। एनएसई जैसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं।

आईटी कंपनियां न सिर्फ देश की

आठ साल बाद जारी हुई सूची, सरकारी नौकरी का रास्ता साफ; 783 आवेदन आए थे

156 को मिला उत्कृष्ट खिलाड़ी का दर्जा

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। कुल 20 खेलों के 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है।इस फैसले से न सिर्फ खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों का सम्मान मिलेगा, बल्कि सरकारी नौकरी में आरक्षित पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी खुल जाएगा।

प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वर्ष 2016 से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। कई वर्षों तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होने से खिलाड़ियों को खेल कोटे में मिलने वाली सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

अब पात्र खिलाड़ियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं, जिससे वर्षों से लंबित प्रक्रिया पूरी हो

गई है।

783 आवेदन आए, कई चरणों में हुई जांच

खेल विभाग को दोनों वर्षों के लिए कुल 783 आवेदन मिले थे। इनमें वर्ष 2018-19 के 344 और वर्ष 2019-20 के 439 आवेदन शामिल थे। शुरुआती जांच के बाद 651 आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए योग्य पाए गए।

इसके बाद उच्चस्तरीय समिति ने सभी दावों और उपलब्धियों की समीक्षा की। अंतिम चयन में 20 अलग-अलग खेलों के 156 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया।

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के बाद इन खिलाड़ियों को प्रदेश के सरकारी विभागों में खेल कोटे का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के दो प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए हैं।

पिछले कई वर्षों से सूची जारी नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्तियां प्रभावित हो रही थीं। अब नई सूची जारी होने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

बैडमिंटन में आकर्षी कश्यप, वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। आर्चरी में धर्मेश गोफने, बिंदेश्वरी मरावी, नित्या धुर्वे, भरत कुमार यादव और आरती मसराम को यह दर्जा मिला है।

इसके अलावा फेंसिंग, हॉकी, कराते, कयाकिंग-कैनोइंग, पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्विमिंग, सॉफ्ट टेनिस, वुशू, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, डेफ स्विमिंग, व्हीलचेयर फेंसिंग और सॉफ्टबॉल समेत कुल 20 खेलों के खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया है।

इस बार हैंडबॉल, व्हीलचेयर फेंसिंग, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल और कयाकिंग-कैनोइंग जैसे खेलों से सबसे अधिक खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वहीं हॉकी से केवल रेणुका यादव, डेफ स्विमिंग से अतुल जायसवाल और सॉफ्ट टेनिस से आयुषी चौहान को उत्कृष्ट खिलाड़ी का दर्जा मिला है।

उत्कृष्ट खिलाड़ी का दर्जा राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को देती है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्धारित मानकों के अनुसार बेहतर प्रदर्शन किया हो।

यह प्रमाणपत्र खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस वजह से प्रदेश के खिलाड़ी पिछले कई वर्षों से इस सूची का इंतजार कर रहे थे।

स्व. तीजन बाई की स्मृति में आयोजित आरुग सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचित

रायपुर। लोककला और पंडवानी परंपरा को समर्पित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति में आयोजित होने वाले आरुग सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन बुधवार को रायपुर प्रेस क्लब में किया गया।

यह सम्मान समारोह 7 अगस्त को शहीद स्मारक, रायपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन अलीम बंसी, तीजन बाई के परिवारजनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। समारोह में लोककला, संस्कृति और पंडवानी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले कलाकारों का सम्मान किया जाएगा तथा स्वर्गीय तीजन बाई के कला-साधना से जुड़े अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा।पोस्टर विमोचन के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी , कोषाध्यक्ष दिनेश यदु सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने प्रदेशवासियों एवं कला प्रेमियों से बड़ी संख्या में समारोह में शामिल होकर स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने की अपील की।

स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का लालटेन मार्च, मीटर बदलने फॉर्म भी बांटे

रायपुर। रायपुर में कांग्रेस ने बुधवार को एक ओर भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के निजीकरण और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर भिलाई बचाओ पदयात्रा निकाली, वहीं शाम को स्मार्ट मीटर के विरोध में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने लोगों को आवेदन फॉर्म बांटकर स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने बिजली मीटर लगाने की मांग का समर्थन किया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह यात्रा बीएसपी से जुड़े कर्मचारियों, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की कथित लापरवाही, अनियमितताओं और जनहित के मुद्दों की अनदेखी के विरोध में

यह अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों से संवाद भी किया। इसके साथ ही पदयात्रा के दौरान स्मार्ट मीटर बदलवाने से जुड़े फॉर्म भी लोगों को बांटे गए।कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता टाटीबंध स्थित भारत माता स्कूल के पास पहुंचे। यहां से पदयात्रा कांग्रेस कार्यालय की ओर निकली। इसके बाद कार्यकर्ता शंकर नगर स्थित राजीव भवन और गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस नेताओं ने उनके राजनीतिक योगदान और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया।

दिन में पदयात्रा और सभा के बाद शाम को कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के विरोध में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, पार्षद अर्जुमन ढेबर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लालटेन लेकर पेंशन बाड़ा स्थित यादव मोहल्ला पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोगों को आवेदन फॉर्म बांटे। उन्होंने कहा कि इन फॉर्मों के माध्यम से उपभोक्ता स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने बिजली मीटर लगाने की मांग कर सकते हैं। नेताओं ने लोगों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

मंत्री राजवाड़े के प्रयासों से 97 गांवों में होगा विद्युत विस्तार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता

दी जा रही है। इसी दिशा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा की विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत भटगांव विधानसभा क्षेत्र के 97 गांवों में विद्युत विस्तार कार्य स्वीकृत किया गया है। लगभग 11.62 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत इस परियोजना के माध्यम से सूरजपुर जिला के दूरस्थ गांवों और मोहल्लों तक विद्युत सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे हजारों ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे।राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत कार्यों में विकासखंड भैयाथान के 36 गांवों के लगभग 109 मोहल्लों/पारों, विकासखंड ओड़गी के 32 गांवों के लगभग 68 मोहल्लों/पारों तथा विकासखंड सूरजपुर के 29 गांवों के लगभग 53 मोहल्लों/पारों में विद्युत विस्तार किया जाएगा।यह परियोजना विशेष रूप से उन ग्रामीण और जनजातीय बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां अब तक पर्याप्त विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्य, पेयजल व्यवस्था, कृषि आधारित गतिविधियों तथा ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य विकास की रोशनी को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वीकृति भटगांव विधानसभा के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी। हर घर और हर आंगन तक बिजली पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी।

रायपुर पश्चिम के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा और स्वास्थ्य का नया अध्याय

रायपुर। शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा समग्र वातावरण है जहाँ बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सम्मान के साथ सीखें और अपने सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास प्राप्त करें। इसी विश्वास को आधार बनाकर रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक विकास अभियान चलाया है।

रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालय आज केवल अध्ययन के केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेरणादायी शिक्षण परिसरों के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के 36 शासकीय

विद्यालयों में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से आधुनिक वॉटर कूलर स्थापित किए गए हैं, जिससे हजारों विद्यार्थियों को वर्षभर स्वच्छ एवं शीतल पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे प्रतिदिन कई घंटे परिसर में व्यतीत करते हैं। विशेषकर भीषण गर्मी के मौसम में स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध न होने से बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। कई बार उन्हें पानी के लिए बार-बार कक्षा से बाहर जाना पड़ता था, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती थी। गर्मी के कारण थकान, निर्जलीकरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी सामने आती थीं।

इन परिस्थितियों को गंभीरता से समझते हुए विधायक राजेश मूणत ने यह निर्णय लिया कि रायपुर पश्चिम का कोई भी विद्यार्थी स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। यही सोच इस पूरी पहल की प्रेरणा बनी।

पर्यटकों के घूमने-फ़िरने की जगहें

आज विद्यालयों में स्थापित आधुनिक वॉटर कूलर केवल पानी उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक हैं। स्वस्थ विद्यार्थी अधिक एकाग्रता, ऊर्जा और उत्साह के साथ अध्ययन करता है तथा उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

रायपुर में 8-9 अगस्त को होगी राज्य स्तरीय गतका स्पर्धा

रायपुर। रायपुर में 8 और 9 अगस्त को तीसरी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय गतका चैंपियनशिप का आयोजन माता सुंदरी खालसा स्कूल, पुराना बस स्टैंड, पंडरी में होगा। द गतका एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में होने वाली इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों से करीब 330 महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी अलग-अलग आयु वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा और आत्मरक्षा कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि गतका सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। यह खेल युवाओं में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करता है। उन्होंने कहा कि यह युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और सीनियर वर्ग के मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परखा जाएगा।

700 शिक्षकों के होंगे ट्रांसफर, तबादला सूची से 400 नाम कटे

रायपुर।शिक्षा विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक स्थानांतरण सूची को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में समन्वय में व्यापक छंटनी की गई है। बताया जा रहा है कि कई नाम निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण सूची से हटा दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) से प्रभावित शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक, जिनके स्थानांतरण से विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकते हैं, अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी नहीं दी गई है। विभाग का मानना है कि ऐसे मामलों में स्थानांतरण से विद्यार्थियों की पढ़ाई और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि शुरुआती दौर में करीब अनुशंसाओ से प्राप्त 1,600 शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए भेजे गए थे। लेकिन सूची में संख्या अधिक होने पर फाइल वापस कर संख्या कम करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार कर भेजी गई। यह सभी नाम नेताओ के अनुशंसा और प्राप्त आवेदन के अनुसार बनाया गया था। बताया जा रहा है कि अंतिम परीक्षण के दौरान इस सूची से भी करीब 400 नाम हटा दिए गए हैं।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

रायपुर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें फिर से 14 अगस्त तक कोल लेवी मामले में ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. इसके साथ शराब घोटाला मामले में उन्हें 19 अगस्त तक ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में रहना होगा. रायपुर के कोर्ट में रामगोपाल अग्रवाल कोल लेवी मामले में 14 अगस्त को पेश होंगे. वही शराब घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल की पेशी कोर्ट में 19 अगस्त को होगी.कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल 3 साल तक फरार रहने के बाद 8 जुलाई 2026 को ईओडब्ल्यू के कार्यालय पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि उनकी भूमिका कथित कोयला घोटाला शराब घोटाला और कस्टम मिलिंग से जुड़े पैसों के प्रबंधन में रही है. जांच कर रही एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है.वहीं, शराब घोटाले की जांच ईडी और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियां कर रही हैं. बुधवार को कोर्ट में रामगोपाल अग्रवाल के जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है. रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड़ के शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला, 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है।

कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर ज्ञान देना हास्यास्पद : डॉ. मिश्रा

रायपुर। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले पांच वर्षों के भूपेश बघेल शासनकाल में छत्तीसगढ़ को अपराध, माफियाराज और भ्रष्टाचार की मण्डी बना दिया था, उसके नेताओं का आज कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाना सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक

बैज द्वारा राज्य की कानून-व्यवस्था पर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए इसे बेहद हास्यास्पद, अवसरवादी और राजनीतिक ढोंग करार दिया है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासनकाल में अपराधियों को खुलकर सत्तावादी संरक्षण प्राप्त था। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का कांग्रेसीकरण ङ्क यही कांग्रेस का वास्तविक राजनीतिक चरित्र रहा है। भूपेश सरकार के समय संगठित गिरोहों, शराब माफिया, सट्टा-जुआ और गांजा-अफीम के अवैध कारोबारियों को जिस तरह से शासकीय और राजनीतिक संरक्षण मिला, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को अपराध की भट्ठी में झोंक दिया था। बैज के आरोपों का करारा जवाब देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि आज जो कांग्रेस नेता नशे के कारोबार और अपराधों की दुहाई दे रहे है।

वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को मिलेगी गति

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को अधिक सक्षम, आधुनिक और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निगम के संचालक मंडल की 56वीं एवं सामान्य सभा की 23वीं बैठक आज निगम मुख्यालय, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर में अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कर्मचारी कल्याण, वित्तीय प्रबंधन और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होने के साथ निगम की कार्यक्षमता और प्रशासनिक दक्षता को भी नई मजबूती मिलेगी। संचालक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) को निगम में यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया।

सेवा सेतु पोर्टल में उत्कृष्ट प्रदर्शनः बलरामपुर के निर्दोष लकड़ा बने प्रदेश के टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई

डिजिटल सेवा विस्तार का एक सफल उदाहरणः ओपी चौधरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासकीय सेवाओं को आमजन तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पहुंचाने की दिशा में लगातार उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सेवा सेतु केंद्र में कार्यरत वीएलई निर्दोष लकड़ा ने वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के टॉप ट्रांजैक्शन वीएलई बनने का गौरव प्राप्त किया है।

रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने श्री निर्दोष लकड़ा को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएं पहुंचाने में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना है।

वर्ष 2025-26 के दौरान श्री निर्दोष

लकड़ा ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 13,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले को गौरवान्वित किया है, बल्कि प्रदेश में डिजिटल सुशासन की दिशा में एक नई मिसाल भी स्थापित की है।

जिले में सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी संचालन के कारण अब ग्रामीण नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित अनेक शासकीय सेवाओं के लिए बार-बार जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर ही सहज, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध हो रही हैं।निर्दोष लकड़ा ने तकनीक का प्रभावी उपयोग, कार्य के प्रति समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ हजारों ग्रामीण परिवारों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। उनका सेवा केंद्र ग्रामीणों के लिए केवल एक सुविधा केंद्र नहीं, बल्कि भरोसेमंद समाधान का माध्यम बन चुका है। सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री निर्दोष लकड़ा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से प्रत्येक नागरिक का जीवन आसान बनाना है।

उन्होंने कहा कि जब लोगों का समय और संसाधन बचते हैं तथा उन्हें बिना किसी परेशानी के सेवाएं मिलती हैं, तभी डिजिटल भारत और सुशासन का उद्देश्य साकार होता है।बलरामपुर जिले में सेवा सेतु पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन एवं डिजिटल सेवा विस्तार की मंशा को धरातल पर साकार करने का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है।

रेणुका गोस्वामी को राष्ट्रपति का विशेष आमंत्रण, विजय शर्मा ने दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर धमतरी जिले की बेटी रेणुका गोस्वामी ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। रेणुका को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की ओर से विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनसे मुलाकात कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर में हुई इस मुलाकात के

दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रेणुका गोस्वामी की सफलता प्रदेश के लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कौशल विकास और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं की प्रभावशीलता का भी प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि रेणुका की यह उपलब्धि अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बिहान और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जैसी पहलें युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से हजारों युवाओं ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.